



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 414]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय: ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथेनॉल और वाटरवेट में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस को छोड़कर नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोस" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/12/2018-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) को ब्राजील, इंडोनेशिया और थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथेनॉल और वाटरवेट में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस को छोड़कर नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोस" जिनमें 10.7 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत तक नाइट्रोजन की मात्रा है (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान कहा गया है) के तथाकथित पाटन के संबंध में मैसर्स नाइट्रस केमिकल इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

और जबकि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत औचित्य बनाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाता है और जो घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति

समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार दिनांक 10.04.2018 की अधिसूचना संख्या 6/12/2018-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

क. सामान्य प्रक्रिया

1. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत अधिसूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग को उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार जांच की शुरुआत की एक प्रति भेजी और जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अनुरोध किया।
- iii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पत्रों सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली तथा पूरक प्रश्नावली भेजी:

क. नोबेल एनसी कंपनी लि.

ख. नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि.

ग. नाइट्रो किमिका ब्राजील

घ. पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसीसी

vi. ब्राजीली निर्यातक नाइट्रो किमिका ब्राजील द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर देने के लिए समय बढ़ाए जाने हेतु अनुरोध दायर किया गया था। प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ाने की मंजूरी दी। तथापि, कोई निर्यातक प्रश्नावली उत्तर नाइट्रो केमिकल ब्राजील की ओर से प्राप्त नहीं हुआ।

vii. जांच की शुरुआत के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए:

क. पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसीसी

ख. पीटी इंटी सेलुलोस उतामा इंडोनेशिया

ग. नोबेल एनसी कंपनी लि.

घ. नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि.

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

क. अकजो नोबेल इंडिया लिमिटेड;

ख. आशा पेन कलर प्रा. लि.;

ग. एसदी पेंट्स लिमिटेड;

घ. फ़िलेंट ग्रुप इंडिया प्रा. लि.

ङ. हाई टेक इंकस प्रा. लि.

च. हिंदुस्तान पेंसिल्स प्रा. लि.

छ. हुबेर ग्रुप इंडिया प्रा. लि.

ज. कनसई नेरोलेक;

झ. सेटको केमिकल्स इंडिया प्रा. लि.

ञ. सीनलेक पेंट्स लिमिटेड;

ट. सीगवर्क इंडिया प्रा. लि.;

ठ. सनशाइन पेंट्स

ड. टाटा पेंट्स;

ढ. वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स

ix. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 07 सितंबर, 2018 के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रश्नावलियां भेजीं:

क. आकार पेंट्स

ख. मैरीगोल्ड पेंट्स;

ग. आइडियल कोटिंग इंडस्ट्रीज;

घ. निप्पो पेंट्स इंडिया लि.

ङ. कनसाई नेरोलेक पेंट्स लि.;

- च. शीनलेक पेंट्स कारपो. पी. लि.;
- छ. हीरो पेंट्स प्रा. लि.;
- ज. अर्चना कलर कोटिंग्स;
- झ. मीट पेंट्स प्रा. लि.;
- ञ. कोकुयो केमलिन लिमिटेड;
- ट. एक्रॉस कोटिंग्स (पी) लि.;
- ठ. कृष्णा मुरारी ऑर्गनसिस;
- ड. जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि.
- x. संबद्ध सामानों के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करके उत्तर दिए:
- क. केम फार्मा इम्पेक्स
- ख. एसडी पेंट्स लि.
- ग. तारा पेंट्स एंड केमिकल्स
- घ. अरिहंत रेसिन्स एंड पिगमेंट्स एलएलपी
- xi. नीचे सूची में दी गई एसोसिएशनों को जांच की शुरुआत की सूचना भेजी गई थी।
- क. इंडिया पेंट्स एंड कोटिंग्स एसोसिएशन;
- ख. इंडिया स्मॉल स्केल पेंट्स एसोसिएशन;
- ग. इंडियन पेंट्स एंड पावर कोटिंग्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन;
- घ. ऑल इंडिया प्रिंटिंग इंक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- xiii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

- xiv. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 6 अगस्त, 2018 को एक मौखिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, थाइलैंड के निर्यातक के प्रतिनिधियों, इंडोनेशिया के निर्यातक के प्रतिनिधियों, इंडोनेशिया के दूतावास, आयातकों और प्रयोक्ताओं ने भाग लिया था। उन सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों को एकत्रित करें और उसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। सुनवाई में उपस्थित प्रयोक्ताओं से उनके लिखित अनुरोधों सहित प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए कहा गया था जिसके बाद निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
- क. एसडी पेंट्स
- ख. अरिहंत पिगमेंट्स एंड रेसिन्स एलएलपी
- xvi. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर विश्वास किया गया है।
- xvii. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2016 – सितंबर, 2017 (18 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 और जांच की अवधि शामिल हैं। जांच की अवधि के आंकड़ों की दूसरे वर्षों से उपयुक्त तुलना करने के लिए, जहां कहीं भी आंकड़े पूरी क्षति अवधि के लिए उल्लिखित किए गए हैं, जांच की अवधि के लिए आंकड़े वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।
- xviii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए हैं, इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिए गए हैं।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें। निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का संशोधित अगोपनीय रूपांतर दायर करने और सभी आवश्यक तथा संगत सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया था। उत्तरदाता निर्यातकों ने प्रश्नावली का संशोधित अगोपनीय रूपांतर दायर किया।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकार्ड की हैं।

- xxi. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को 07 दिसंबर, 2018 को अनिवार्य तथ्य प्रकट किए गए थे। टिप्पणियां 14 दिसंबर, 2018 तक मांगी गई थीं। प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiii. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.06 रुपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 घरेलू उद्योग के विचार

2. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद एथेनॉल और वाटरवेट में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस को छोड़कर नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोस जिनमें 10.7 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत तक नाइट्रोजन की मात्रा है (जिसे आगे पीयूसी कहा जाएगा), है।
- ii. औद्योगिक नाइट्रोसेलुलोस दो किस्म का है, एक घुलनशील (घुलनशील डैम्पड) अर्थात् नॉन-प्लास्टिसाइज्ड नाइट्रोसेलुलोस है और दूसरा प्लास्टिसाइजर डैम्पड है। नॉन-प्लास्टिसाइज्ड नाइट्रोसेलुलोस मूल रूप से घुलनशील डैम्पड आधारित नाइट्रोसेलुलोस है जिसका प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया जाता है।
- iii. तीन किस्म के डैम्पिंग मीडिया हैं अर्थात् नॉर्मल बुटाइल एल्कोहॉल (एनबीए) डैम्पड, एसोप्रोपिल एल्कोहॉल (आईपीए) डैम्पड और एथाइल एल्कोहॉल डैम्पड तथा नॉन-प्लास्टिसाइज्ड नाइट्रोसेलुलोस की चौथी किस्म वाटरवेट है जिसे किसी मीडियम में डैम्पड किया जा सकता है।
- iv. आईपीए में डैम्पड नॉन-प्लास्टिसाइज्ड नाइट्रोसेलुलोस (एनसी) तथा एनबीए में डैम्पड एक ही कार्य करता है और प्रिंट उद्योग के लिए परस्पर परिवर्तनीय है।
- v. विचाराधीन उत्पाद सख्ती, टिकारूपन, तीव्र घुलनशीलता छोड़ने की क्षमता और घुलनशीलता जैसे गुणधर्मों में असमान एक सबसे पुराने फिल्म निर्माता के रूप में जाना जाता है।
- vi. विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख कच्ची सामग्री पल्प अर्थात् सेलुलोस है जो कॉटन लिंटर अथवा ऊन पल्प के रूप में शुद्ध किए गए सेलुलोस से प्राप्त की जाती है।
- vii. विचाराधीन उत्पाद "इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोस डैम्पड इन एसोप्रोपिल एल्कोहॉल" है और उसे किलोग्राम में मापा जाता है तथा सीमा शुल्क उप शीर्ष 39122019 के तहत वर्गीकृत है।
- viii. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद में और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। उपभोक्ता दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातित सामानों की समान वस्तु हैं।

- ix. विचाराधीन उत्पाद कच्ची सामग्री के रूप में ऊन पल्प तथा कॉटन लिंटर से उत्पादित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा कच्ची सामग्री का चयन उनकी कीमतों अथवा जलवायु की स्थितियों के आधार पर किया जाता है। कच्ची सामग्री की कोई कमी नहीं थी और घरेलू उद्योग को इस कारण कभी भी क्षति नहीं हुई।
- x. याचिकाकर्ता द्वारा बेचे जा रहे विचाराधीन उत्पाद में कोई गुणवत्ता का मुद्दा नहीं है क्योंकि एसडी पेंट्स जैसे प्रयोक्ता याचिकाकर्ता से विचाराधीन उत्पाद की खरीद विगत 25 वर्षों से करते आ रहे हैं और उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कभी कोई शिकायतें नहीं की हैं।
- xi. प्रयोक्ता बेहतर गुणवत्ता के कारण आयातों में नहीं गए हैं बल्कि उनके द्वारा पेश की जा रही सस्ती कीमतों के कारण गए हैं। अतः गुणवत्ता के संबंध में आरोप पूर्णतः आधारहीन है और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और मात्र आरोप लगाया है।
- xii. याचिकाकर्ता कई एमएनसी और भारतीय कंपनियों, लगभग सभी छोटे पैमाने की कंपनियों और विश्व में 25 से अधिक देशों की पूर्ति करता है। यह सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नाइट्रस की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों की है।
- xiii. विचाराधीन उत्पाद की पैकिंग की गुणवत्ता कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब याचिकाकर्ता द्वारा दी गई पैकेजिंग पूर्णतः सुरक्षित है।

ख. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की गुणवत्ता संबद्ध आयातों की तुलना में कम गुणवत्ता की है।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक है तथा घरेलू उद्योग सामग्री को घटिया पैकिंग बोर्डों में पैक करता है जबकि आयातित उत्पाद फाइबर बोर्ड की सामग्री में समुचित रूप से पैक किया जाता है।
 - iii. उत्पाद की गुणवत्ता उसके रंग से निर्धारित की जाती है और यह उत्पाद सफेद रंग के कॉटन के रूप का है, परंतु घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद रंग में पीला है जो घटिया गुणवत्ता दर्शाता है।
 - iv. आयातित उत्पाद अधिक मुक्त रूप से प्रवाहित होने वाला है, इस प्रकार सार संभाल करने के लिए आसान है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद स्वतंत्र रूप से कम प्रवाहित होने वाला है और सार संभाल करने के लिए कठिन है।

ख. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एथेनॉल और वाटरवेट में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस को छोड़कर नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोस जिनमें 10.7 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत तक नाइट्रोजन की मात्रा है (जिसे आगे नाइट्रोसेलुलोस और संबद्ध सामानों के रूप में भी वर्णित किया गया है), है।
- 5. विचाराधीन उत्पाद में सख्ती, टिकाऊपन, तीव्र घुलनशीलता छोड़ने की क्षमता और घुलनशीलता जैसे गुणधर्म हैं। विचाराधीन उत्पाद नाइट्रिक एसिड अथवा दूसरे शक्तिशाली नाइट्रेटिंग एजेंट में रखकर नाइट्रेटिंग सेलुलोस द्वारा

निर्मित एक ज्वलनशील सम्मिश्रण है और इसका प्रयोग वुड लेकर्स, ऑटो रिफिनिश पेंट्स, लैडर फिनिशिंग लैकर्स, नैल वार्निश और पेंटिंग इंक आदि के विनिर्माण में किया जाता है। इस उत्पाद का किसी भी निचले उत्पाद की उत्पादन लागत में भारी अनुपात नहीं होता है।

6. विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख कच्ची सामग्री पल्प अर्थात् सेलुलोस है जो कॉटन लिंटर अथवा ऊन पल्प के रूप में शुद्ध किए गए सेलुलोस से प्राप्त की जाती है। यद्यपि, इस उत्पाद का वजन 70 प्रतिशत नाइट्रोसेलुलोस होता है, यह उपयुक्त घोलक (30 प्रतिशत) में डैम्पड बेचा जाता है ताकि नाइट्रोसेलुलोस को जलने से बचाया जा सके। प्राधिकारी ने नोट किया है कि यदि नाइट्रोसेलुलोस को पेंट और वार्निश उद्योग के लिए एसोप्रोपिल एल्कोहॉल (आईपीए) में प्रयोग के लिए सामान्य रूप से डैम्पड किया जाता है, तथापि, यह अधिकतर केवल भारत में है कि नॉर्मल बुटाइल एल्कोहॉल (एनबीए) में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस का भी प्रयोग किया जाता है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान एनबीए में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस का संबद्ध देशों से भारत में कोई व्यापार/आयात नहीं हुआ है।
7. तथापि, यह मानते हुए कि एनबीए और आईपीए के बीच काफी कीमत संबंधी अंतर है, "एनबीए अथवा बुटानोल में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस" का कोई आयात नहीं है, संबद्ध देशों में "एनबीए में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस" का कोई ज्ञात उत्पादन नहीं है तथा "एनबीए में डैम्पड नाइट्रोसेलुलोस" की सीमित परस्पर परिवर्तनीयता है और आईपीए में डैम्पड हैं, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल "10.7 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत की दर में नाइट्रोजन की मात्रा वाले एसोप्रोपिल एल्कोहॉल में डैम्पड नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेलुलोस तक प्रतिबंधित किया है।
8. संबद्ध सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 3912 के तहत अध्याय 39 शीर्ष के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि इस उत्पाद को 39122019 के सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत सूचित किया गया है।
9. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में चिंता जताई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच तथाकथित गुणवत्ता संबंधी अंतर दर्शाने के लिए इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई उपयुक्त साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य दिए हैं कि कुछ ग्राहकों ने आयातों से अपने स्रोत बढ़ाए हैं और घरेलू उद्योग से कम किए हैं। तथापि, ये ग्राहक घरेलू उद्योग से काफी मात्रा में खरीद करते रहे, इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये पक्षकार फिर भी घरेलू उद्योग से उत्पाद की काफी मात्रा खरीद रहे थे। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग और थाइलैंड के निर्यातक के परिसरों में किया गया स्थल सत्यापन घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद और विदेशी उत्पादकों के उत्पाद में कोई वास्तविक अंतर नहीं दर्शाता। घरेलू उद्योग से अधिक कीमतों की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक कीमतों पर खरीद जारी रखना भी यह दर्शाता है कि उपभोक्ता विदेशी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कम कीमतों के कारण आयातों की ओर गए हैं, न कि उत्पाद की गुणवत्ता में तथाकथित अंतर के कारण।
10. जहां तक उत्पाद की पैकेजिंग की गुणवत्ता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि पैकेजिंग में अंतर भिन्न उत्पादों के रूप में दोनों उत्पादों को कैसे रखता है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता उत्पाद की बिक्री पिछले कुछ समय से करता रहा है और यह दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय साक्ष्य नहीं है कि पैकेजिंग की गुणवत्ता में अंतर से अधिक आयात हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि वह माइल्ड स्टील ड्रमों में उत्पाद की आपूर्ति करता है जिसे कि फाइबर गोल्ड ड्रम पैकिंग तथा आयातों की कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग उत्पाद का निर्यात करता रहा है और उसका निर्यात वर्तमान जांच की अवधि में दोगुना हो गया।
11. समान वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:

“ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।”

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों के तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।
13. इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

ग. 1 घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. प्राधिकारी विस्तृत जांच करें और याचिकाकर्ता के आधा का पता करें। याचिकाकर्ता को कुछ नहीं कहना है। तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करेंगे कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में प्रमुख उत्पादन है।
 - ii. अन्य सभी उत्पादकों का संचयी उत्पादन इस कारण भ्रामक होगा कि एक उत्पादक ने अलग-अलग समय में अपना उत्पादन आरंभ किया है और मैसर्स यूनिक्स सेलुलोस प्रा. लि. ने क्षति की अवधि में ही उत्पादन आरंभ किया है।

ग. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. भारत में विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादक अर्थात् जीआरएन सेलुलोस प्रा. लि. और यूनिक्स सेलुलोस प्रा. लि. हैं। इस प्रकार, यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता का भारत में उत्पादन का "प्रमुख हिस्सा" है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. यह आवेदन पत्र संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक के रूप में मैसर्स नाइट्रस केमिकल इंडिया लि. द्वारा दायर किया गया है जिन्होंने वर्तमान जांच के लिए विस्तृत सूचना प्रदान की है। याचिकाकर्ता ने जीआरएन सेलुलोस प्रा. लि. और यूनिक्स सेलुलोस प्रा. लि. को उत्पाद का अन्य भारतीय उत्पादक के रूप में अभिज्ञात किया। भारत में संबद्ध सामानों का अन्य कोई ज्ञात उत्पादक नहीं है।
17. प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनाने वाले याचिकाकर्ता की जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क पर विचार किया। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया है। यह

नोट किया जाता है कि सूचित किए गए दो "अन्य उत्पादकों" ने वर्तमान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यद्यपि एक पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन कर रहा था, तथापि, दूसरे ने 2015-16 में उत्पादन आरंभ किया। यह सूचना याचिकाकर्ता द्वारा दी गई थी, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इन उत्पादकों के संबंध में कोई विशेष आंकड़े/सूचना नहीं दी है। अतः प्राधिकारी ने उनके समक्ष सूचना के आधार पर कुल भारतीय उत्पादन की मात्रा निकाली है और यह निर्धारित किया है कि जांच की अवधि में याचिकाकर्ता का उत्पादन 71 प्रतिशत था जबकि अन्य दो घरेलू उत्पादकों का उत्पादन शेष 29 प्रतिशत था।

18. याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध है। इस प्रकार, विभिन्न संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता कानून के तहत घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पात्र है और भारतीय उत्पादन में उसके उत्पादन का प्रमुख अनुपात है।
19. इस प्रकार, यह निर्धारित किया जाता है कि यह याचिका घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दी गई है, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के तहत "आधार" की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" है।

घ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

घ. 1 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. उत्तरदाता निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता के दावों का सहारा लिया है जिससे याचिकाकर्ताओं को उनकी टिप्पणियां पेश करने से वे रुके हैं। गोपनीयता के दावे नियमावली के नियम 7 के अनुसार नहीं हैं।
 - ii. किसी भी पक्षकार ने अपने निष्पादन संकेतकों का सूचीबद्ध रूपांतर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर क्षति संबंधी विवरण या तो वास्तविक आधार पर है या सूची के आधार पर है।
 - iii. वर्तमान मामले में, सूचना को आसानी से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसके बावजूद, सूचना पूरी तरह छिपाई गई है।
 - iv. याचिकाकर्ता द्वारा दायर क्षति संबंधी विवरण देखा जा सकता है। घरेलू उद्योग ने एक मात्र कंपनी होने के नाते क्षति संबंधी मानदंडों की प्रवृत्ति दर्शाते हुए प्रत्येक मानदंड के सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं, निर्यातकों ने परिशिष्ट-1 में मांगे गए अनुसार निष्पादन मानदंडों का अगोपनीय सार भी नहीं देने का विकल्प चुना।
 - v. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी पूरी सूचना प्रकट नहीं की है जिसे वे नियमावली के अनुसार प्रकट करने के लिए बाध्य हैं। यहां तक कि जो सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, अगोपनीय रूपांतर में प्रकट नहीं की गई है।
 - vi. प्रयोक्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है और गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का सार बताने के लिए पर्याप्त सूचना से युक्त एनसीवी प्रयोक्ता प्रश्नावली दायर नहीं की है। घरेलू उद्योग अपने हित की रक्षा करने और उनके द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं है।

- vii. व्यापार सूचना संख्या 05/2018 दिनांक 28 फरवरी, 2018 में यह उल्लिखित है कि हितबद्ध पक्षकारों को दायर प्रत्येक गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार दायर करना अपेक्षित है।

घ. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

23. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की गई है तथा तदनुसार उन्हें हल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो सूचना सार्वजनिक पटल रप उपलब्ध है, उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी ने निर्यातकों को निर्देश दिया कि वे प्रश्नावली का संशोधित अगोपनीय रूपांतर दायर करें और सार्थक उत्तर दें। उत्तरदाता निर्यातकों ने संशोधित उत्तर दायर किया। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

ङ. विविध अनुरोध

ङ. 1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. विरोधी पक्षकारों का आरोप स्थिति का केवल आधा सच बताता है और संयंत्र की बंदी का उल्लेख करने वाला समाचार अनुच्छेद जांच की अवधि के अंतर्गत नहीं आता।

- ii. याचिकाकर्ता का संयंत्र की बंदी का आरोप आधारहीन है। याचिकाकर्ता ने संयंत्र की बंदी के संबंध में पूरे ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।
- iii. याचिकाकर्ता ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के सुझाए गए उपचारों के संबंध में कार्रवाई की और इस प्रकार उन्होंने 15 दिन में उस आदेश को वापस लिया। इसके अतिरिक्त, नाइट्रस प्लांट विनियामक मुद्दों पर कभी बंद नहीं था।
- iv. याचिकाकर्ता के संयंत्र में पानी की कमी के संबंध में विरोधी पक्षकार के आरोप का कोई संबंध नहीं है। गुजरात सरकार, नगरपालिका और सिंचाई विभाग के साथ याचिकाकर्ता का सतत करार स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पास पानी की कमी नहीं है और वे पर्याप्त रूप से जलापूर्ति प्राप्त करते हैं। इसका साक्ष्य रिकार्ड में दायर किया गया है।
- v. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (मार्च, 2013) और उसकी संगत धाराएं, जो पानी की पर्याप्त आपूर्ति की गारंटी लेते हैं।
- vi. जल की औसत दैनिक खपत यह दर्शाती है कि जल की औसत दैनिक उपलब्धता (पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति माह) याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित से अधिक थी।
- vii. जांच की अवधि अप्रैल, 2016 – सितंबर, 2017 है और जांच की शुरुआत 10 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। जांच की अवधि और जांच की शुरुआत के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है। जांच की शुरुआत के लिए दिए गए आंकड़े हाल के थे और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच की गई है।
- viii. संबद्ध देशों में विभिन्न प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाएं हैं जिनके कारण भारत को मुक्त बाजार पहुँच नहीं दी जाती है। तथापि, भारत काफी शुल्क रियायतों के साथ और किसी लाइसेंस की आवश्यकता के बिना इन निर्यातकों के लिए खुला बाजार है।
- ix. थाइलैंड और इंडोनेशिया ने जांच की अवधि में लगभग 300 टन नाइट्रोसेलुलोस का निर्यात किया है जबकि भारतीय उत्पादकों को गैर-प्रशुल्क बाधा के कारण इन देशों द्वारा मुक्त बाजार पहुँच नहीं दी गई है।
- x. नाइट्रोसेलुलोस (सिविल और रक्षा प्रयोग, दोनों के लिए) "थाई रक्षा मंत्रालय सेनांग" की अधिसूचना के तहत "विस्फोटक वस्तु" के रूप में सूचीबद्ध है। परिणाम के रूप में औद्योगिक नाइट्रोसेलुलोस के आयात के लिए "हथियार नियंत्रण अधिनियम" के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- xi. मुक्त व्यापार करार के अनुसार, इंडोनेशिया से भारत में वर्तमान आयात एमएफएन श्रेणी के तहत शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क वाले हैं। तथापि, भारत से इंडोनेशिया में आयातों पर 4 प्रतिशत सीमा शुल्क है।
- xii. ब्राजील में भारतीय उत्पादकों को आयात लाइसेंस प्राप्त करना होगा जहां रक्षा मंत्रालय, ब्राजील शामिल है और आयात लाइसेंस सार्वजनिक सुरक्षा के तर्क पर मना कर दिया जाता है तथा विस्फोटकों के उत्पादन के लिए रसायन का प्रयोग किया जा सकता है।
- xiii. संबद्ध सामानों के लिए ब्राजील के लिए भारत को सीमा शुल्क 7.25 प्रतिशत है जबकि भारतीय आयातों को ब्राजील में 14 प्रतिशत सीमा शुल्क देने की आवश्यकता होती है। अतः ब्राजील में भारतीय आयात प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधा, दोनों के अध्याधीन हैं।

- xiv. एबीसी केमिकल्स प्रा. लि. द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय सीमा के बाद विलंब से था। आयातक द्वारा प्रश्नावली प्राधिकारी द्वारा उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बावजूद 49 दिन के विलंब के बाद दायर की गई थी।
- xv. प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा के संबंध में, बहुत सावधान रहे हैं और एक बार प्राधिकारी ने केवल 24 घंटे से अधिक के विलंब के लिए याचिकाकर्ता को रद्द किया है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी के आलोक में एबीसी केमिकल द्वारा दायर उत्तर रद्द किया जाना चाहिए।
- xvi. केम फार्मा द्वारा दायर आयातक प्रश्नावली को काफी विलंब के स्तर पर दायर किए जाने के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। प्रश्नावली का उत्तर दायर करने का अवसर केवल प्रयोक्ताओं को है।

ड. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. याचिकाकर्ता के संयंत्र विनियामक मुद्दों के कारण राज्य प्राधिकारियों द्वारा दो बार बंद किए गए हैं। इस प्रकार, निष्पादन में गिरावट और बाद में क्षति को संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।
- ii. याचिकाकर्ता के दो संयंत्र गुजरात में हैं और गुजरात राज्य में पानी की कमी है। याचिकाकर्ता को कई वर्षों से जल की कमी के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है जिससे याचिकाकर्ता का उत्पादन प्रभावित हुआ है जो याचिकाकर्ता के उद्योग निष्पादन को प्रभावित करने वाला प्रभावी कारक होना चाहिए।
- iii. याचिकाकर्ता किसी सूचना के बिना उत्पाद की आपूर्ति रोक देता है।
- iv. जांच की अवधि हाल की नहीं है और जांच की शुरूआत की तारीख तथा जांच की अवधि के बीच 6 माह का अंतराल है। जांच की अवधि संशोधित की जानी चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध कि वे जून, 2018 तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करें।
- v. इंडोनेशियाई उद्योग यह विश्वास करता है कि यह वर्तमान जांच में संगत है। इसके अतिरिक्त, सभी एफटीए के तहत प्रशुल्क का निर्णय उनके संबंधित उद्योग के हित पर पूरा विचार करके शामिल सरकार के आर्थिक विचार के आधार पर लिया गया है।
- vi. आसियान के कारण प्रशुल्क अंतर का तथ्य वर्तमान जांच के लिए संगत है। करार उनके संबंधित उद्योग के हित पर पूरा विचार करके शामिल सरकार के आर्थिक विचार को देखते हुए सरकार द्वारा किए जाते हैं।
- vii. कोई शुल्क लगाना प्रयोक्ता उद्योग के लिए भारतीय बाजार में उच्चतर कीमतों के कारण संबद्ध सामानों की खरीद करना कठिन हो जाएगा।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न विविध मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता राज्य प्राधिकारियों द्वारा दो बार उनके संयंत्र को बंद किए जाने के कारण बहुत बुरी तरह से निष्पादन कर रहा है, घरेलू उद्योग ने इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए

साक्ष्यों पर विचार किया और यह नोट किया जाता है कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने याचिकाकर्ता को संयंत्र बंदी का नोटिस जारी किया था; तथापि, याचिकाकर्ता ने नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया। संयंत्र बंद करने का नोटिस हटाया गया था और संयंत्र उस कारण कभी बंद नहीं था।

27. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के संयंत्र में पानी की कमी के संबंध में मुद्दे की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने नगर पालिका और सिंचाई विभाग, गुजरात सरकार के साथ उनका करार प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त जलापूर्ति है और कोई संयंत्र अथवा उत्पादन जल की कमी के कारण बंद नहीं है।
28. यह भी नोट किया जाता है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो यह सिद्ध करे कि याचिकाकर्ता ने पूर्व सूचना के बिना अचानक ही उत्पाद की आपूर्ति रोकी अथवा बंद की।
29. जहां तक संबद्ध देशों में गैर प्रशुल्क बाधाओं के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी थाइलैंड और ब्राजील में इन गैर प्रशुल्क बाधाओं के संबंध में घरेलू उद्योग की चिंताओं को नोट करते हैं। तथापि, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह मुद्दा वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर का है। हितबद्ध पक्षकार इन मुद्दों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान जांच का प्रयोजन यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात किया जाता रहा है और क्या उससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
30. जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी इसे पाटनरोधी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। प्राधिकारी का इरादा घरेलू प्रयोक्ता उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त किसी अनुचित परिपाटी को हल किया जाए और सर्वोत्तम रूप से उस सीमा तक जहां तक इन परिपाटियों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। घरेलू प्रयोक्ता उद्योग के हितों पर इसमें यह सुनिश्चित करने के व्यापक संदर्भ में विचार किया जाएगा कि घरेलू बाजार में उचित और समान स्थितियां बनी रहें।
31. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विलंब से दायर उत्तरों के संबंध में यद्यपि प्राधिकारी जांच के प्रयोजन के लिए समय सीमा की महत्ता का उल्लेख करते हैं, तथापि, इन उत्तरों में उठाए गए संगतता के मुद्दों पर यथा संभव सीमा तक विचार किया गया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

32. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

- i. थाइलैंड से सीआईएफ आयात कीमत, जो अन्य संबद्ध देशों से अधिक प्रतीत होती है, वास्तविक आयात कीमत नहीं है क्योंकि थाइलैंड के कई उत्पादकों/निर्यातकों को सीआईएफ आयात कीमत पर विशेष छूटें प्राप्त होती हैं। यह कुछ ग्राहकों के साथ कीमत वार्ताओं संबंधी पत्राचार से सिद्ध हुआ।

च. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. भारत में थाइलैंड से कीमतें अन्य देशों से कीमतों की अपेक्षा अधिक रही हैं।

- ii. सहयोगी निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित सूचना दायर की है और निर्यातकों को अलग मार्जिन प्रदान करने के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए।
- iii. वितरण स्तर पर हुए किसी संभावित व्याज सहित किसी लागू कर, सार संभाल प्रभार और अंतर्देशीय परिवहन जैसे विभिन्न लागत संबंधी कारकों पर पहुँच कीमत के लिए विचार नहीं किया गया है।
- iv. इंडोनेशियाई बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्द्धा यह दर्शाती है कि इंडोनेशियाई उद्योग के अपनी कीमत अधिक रखने की संभावना नहीं है, परंतु हमेशा बहुत ही प्रतिस्पर्द्धी स्तर पर रखने की है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि भारत में इंडोनेशिया उद्योग का निर्यात कीमत स्तर डब्ल्यूटीओ के उचित व्यापार मानदंडों के अनुसार उचित है।
- v. इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का लागत ढांचा उत्पादन, विद्युत और श्रम में प्रयुक्त कच्ची सामग्री सहित इंडोनेशिया का प्रतिनिधि कारक होगा। यह अपूर्ण अवधारणा इंडोनेशियाई उत्पादक की वास्तविक लागत और बिक्री को नहीं दर्शा सकता। इस प्रकार, पाटन का यह आरोप पाटन जांच में साक्ष्य के रूप में प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता और डीजीएडी को इस अवधारणा को रद्द करना चाहिए।
- vi. बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट के कारण है। घरेलू उद्योग पर कीमत संबंधी कोई प्रभाव नहीं है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. वस्तु के संबंध में धारा 9क(1)(ग) के तहत सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

35. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह देते हुए उन्हें प्रश्नावलियां भेजीं। निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- क. पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी
- ख. पीटी इंटी सेलुलोस उतामा इंडोनेशिया

ग. नोबेल एनसी कं. लि.

घ. नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि.

36. चूंकि, उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, अतः प्राधिकारी सहयोगी निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं। इन निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया सामान्य सिद्धांत पहले यह जांच करने का है कि क्या उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा संबद्ध सामानों की उनके घरेलू बाजारों में घरेलू बिक्री प्रतिनिधिकारक थीं और घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अर्थक्षम थीं और क्या बाजार परीक्षण की सामान्य अवधि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार संतोषजनक थी।
37. संबद्ध देशों में असहयोगी निर्यातकों के मामले में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
38. प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

च. 4 इंडोनेशिया के निर्यातकों के लिए पाटन का मूल्यांकन

(क) पीटी इंटी सेलुलोसोटामा, इंडोनेशिया (उत्पादक) और पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी (निर्यातक) का सामान्य मूल्य

39. पीटी इंटी सेलुलोसोटामा, इंडोनेशिया संबद्ध सामानों का उत्पादक है और अपनी संबद्ध कंपनी पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी के माध्यम से भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहा है। पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी इंडोनेशिया गुणराज्य के कानून के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है और विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र निर्यातक है तथा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक नहीं है। पीटी इंटी सेलुलोसोटामा और उसके संबद्ध निर्यातक पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी इंडोनेशिया द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और यह देखा जाता है कि पीटी इंटी सेलुलोसोटामा सीधे ही घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री नहीं करता। वह घरेलू बाजार में संबद्ध पक्षकार पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी के माध्यम से 100 प्रतिशत संबद्ध सामानों का बेचता है। विचाराधीन उत्पाद की बिक्री संबद्ध पक्षकार पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी द्वारा इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में की जाती है। अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत जैसे खर्चों का समायोजन विदेशी उत्पादक के देश में घरेलू बिक्री कीमत के निर्धारण के निमित्त किया गया है। जांच की अवधि के दौरान पीटी इंटी सेलुलोसोटामा ने पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी के माध्यम से घरेलू बाजार में 3351.69 मी. टन संबद्ध सामानों की बिक्री की। ये सभी बिक्रियां व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि के अध्यधीन थीं। यह पाया गया कि घरेलू बाजार में 94 प्रतिशत बिक्री लाभप्रद थी। तदनुसार, कुल बिक्री के आधार पर उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निकाला गया सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन है।

(ख) पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी (संबद्ध निर्यातक) के माध्यम से निर्यातित पीटी इंटी सेलुलोसोटामा, इंडोनेशिया की निर्यात कीमत

40. यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने भारत को सभी निर्यात पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी (संबद्ध निर्यातक) के माध्यम से सीधे ही किए हैं। यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्यातक ने भी उत्तर दायर किए हैं। प्राधिकारी उत्पादक और निर्यातक, दोनों दायर उत्तरों की जांच करने पर यह नोट करते हैं कि पीटी इंटी सेलुलोसोटामा ने पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी के माध्यम से 849.05 मी. टन का निर्यात किया। निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय

परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबंधित खर्चों, ऋण लागत और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है। निर्यातक ने उल्लेख किया है कि इन खर्चों के लिए समायोजन का वास्तविकता के आधार पर दावा किया गया है। प्राधिकारी ने उनके द्वारा अपने उत्तर में दावा किए गए सभी समायोजनों सहित निर्यात कीमत स्वीकार की है। इस प्रकार, निर्धारित निर्यात कीमत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त की गई है।

(ग) इंडोनेशिया के अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक

41. इंडोनेशिया के अन्य सभी निर्यातकों, जिन्हें असहयोगी माना गया है, के संबंध में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की।

च. 5 थाइलैंड के निर्यातकों के लिए पाटन का मूल्यांकन

(क) नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. और नोबेल एनसी कं. लि. का सामान्य मूल्य।

42. नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. और नोबेल एनसी कं. लि., थाइलैंड द्वारा प्रभावली के उत्तर दायर कर दिए गए हैं। नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है और एक धारक कंपनी है। नोबेल एनसी भी संबद्ध सामान का उत्पादक है और नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली है। दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने उत्तर के परिशिष्ट-4 में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री कीमत के ब्यौरे दिए हैं। नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. थाइलैंड में घरेलू बाजार में सीधे ही ग्राहकों को संबद्ध सामानों की बिक्री करती है। अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण प्रभार, ऋण लागत और अन्य खर्चों जैसे व्ययों का समायोजन विदेशी उत्पादक के देश में घरेलू बिक्री कीमत के निर्धारण के निमित्त किया गया है। नोबेल एनसी धारक कंपनी नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री के माध्यम से घरेलू बाजार में 100 प्रतिशत संबद्ध सामानों की बिक्री करती है। अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत, भंडारण लागत और अन्य व्यय जैसे खर्चों का समायोजन विदेशी उत्पादक के देश में घरेलू बिक्री कीमत के निर्धारण के निमित्त किया गया है। ये सभी बिक्रियां व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि के अध्यधीन थीं। यह पाया गया कि घरेलू बाजार में 99.96 प्रतिशत बिक्री लाभ पर थी। तदनुसार, कुल बिक्री के आधार पर उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निकाला गया सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन है।

(ख) नोबेल एनसी कं. लि. के माध्यम से नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. की निर्यात कीमत

43. यह नोट किया जाता है कि नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. ने भारत को सीधे ही तथा नोबेल एनसी कं. लि. (संबद्ध निर्यातक) के माध्यम से सभी निर्यात किए हैं। संबंधित निर्यातक/उत्पादक नोबेल एनसी ने सभी संबद्ध सामानों का भारत को निर्यात सीधे ही किया है। अतः प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन से संबंधित निर्यातक के माध्यम से निर्यात तथा सीधा निर्यात दोनों को ध्यान में रखा है। निर्यातक/उत्पादकों ने पोत परिवहन लागत, समुद्री, सार संभाल प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, भंडारण लागत, कमीशन, ऋण लागत, बैंक प्रभार और अन्य खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है। निर्यातक/उत्पादक ने उल्लेख किया है कि इन खर्चों के लिए समायोजन का वास्तविकता के आधार पर दावा किया गया है। प्राधिकारी ने उनके द्वारा अपने उत्तर में दावा किए गए सभी समायोजनों सहित निर्यात कीमत स्वीकार की है। इस प्रकार, निर्धारित निर्यात कीमत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त की गई है।

(ग) थाइलैंड के अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक

44. थाइलैंड के अन्य सभी निर्यातकों, जिन्हें असहयोगी माना गया है, के संबंध में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की।

च. 6 ब्राजील के निर्यातकों के लिए पाटन का मूल्यांकन

45. चूंकि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः ब्राजील के सभी निर्यातकों/उत्पादकों को असहयोगी माना गया है। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने ब्राजील से तीसरे देश को नाइट्रोसेलुलोस की निर्यात कीमत के आधार पर ब्राजील के सामान्य मूल्य का दावा किया था। चूंकि, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई कीमतें नाइट्रोसेलुलोस की हैं और उत्पाद का और विभाजन उपलब्ध नहीं है तथा चूंकि, नाइट्रोसेलुलोस का उत्पादन एवं बिक्री विभिन्न रूपों में की जाती है, यद्यपि जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए यह साक्ष्य पर्याप्त था, अतः उसे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अतः प्राधिकारी ब्राजील में उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत से संबंधित किसी सार्वजनिक सूचना के अभाव में एसजीए और लाभों के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ उत्पादन लागत के सर्वोत्तम आकलन के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं।
46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिसका प्रयोग निर्यात कीमत और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जा सके। अतः प्राधिकारी ने ब्राजील में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और कमीशन निमित्त कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समायोजित किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।
47. ऊपर बताए गए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर संबद्ध देशों में उत्तरदाता और उत्तर न देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है जिसके ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातक	देश	एनवी/सीएनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		
			अमेरिकी डॉलर/मी. टन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
1	नाइट्रो केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड/नोबेल एनसी कं. लि.	थाइलैंड	***	***	***	** *	40- 50
2	क्रम सं. 1 को छोड़कर कोई अन्य	थाइलैंड	***	***	***	** *	65- 75
3	पीटी इंडी सेलुलोसटामा	इंडोनेशिया	***	***	***	** *	05- 15
4	क्रम सं. 3 को छोड़कर कोई अन्य	इंडोनेशिया	***	***	***	** *	20- 30
5	सभी उत्पादक	ब्राजील	***	***	***	** *	50- 60

छ. क्षति निर्धारण के लिए सिद्धांत तथा क्षति की जांच एवं कारणात्मक संपर्क**छ. 1 घरेलू उद्योग के विचार**

48. जहां तक क्षति और कारणात्मक संपर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद की मांग पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है। वह आधार वर्ष से जांच की अवधि में 44 प्रतिशत तक बढ़ी है।
- ii. संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं। संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा भारत में कुल आयातों का लगभग 97 प्रतिशत है। क्षति की अवधि में भारत में उत्पादन एवं मांग की तुलना में आयात भी बढ़े हैं।
- iii. मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है। यहां तक कि आयात मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए हो रहे हैं तो निर्यात उचित कीमत पर उस उत्पाद की बिक्री कर ऐसा कर सकते हैं। मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन का औचित्य नहीं बनाता।
- iv. याचिकाकर्ता ने विगत चार वर्षों में कई प्रमुख ग्राहकों को बिक्री खोई है। कई प्रमुख ग्राहकों जो घरेलू उद्योग से संबद्ध सामानों की खरीद कर रहे थे, ने आयातों द्वारा पेश की गई पाटित कीमतों के कारण या तो पूर्णतः या तो आंशिक रूप से आयातों में जाना बेहतर माना।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की हानि बाजार की खराब प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई प्रतिकूल कीमतों के बावजूद है। यदि याचिकाकर्ता ने इन ग्राहकों को नहीं खोया होता तो वह और अधिक बिक्री कर सकता था। याचिकाकर्ता को ग्राहकों की हानि के कारण काफी मात्रा तक क्षति हुई है।
- vi. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण काफी कीमत कटौती हुई है।
- vii. जांच की अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई। घरेलू उद्योग बाजार में बने रहने के लिए संबद्ध देशों की आयात कीमतों से मेल खाने के लिए बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर था। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास कर रहे हैं।
- viii. प्रत्येक संबद्ध देश से काफी कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- ix. जांच की अवधि में उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता अनुचित व्यापारिक परिपाटियों का सामना कर रहा है। याचिकाकर्ता को निर्यातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है और जांच की अवधि में निर्यात बढ़े हैं।
- x. विचाराधीन उत्पाद की मांग आधार वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत तक और पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत तक बढ़े हैं जबकि घरेलू बिक्री क्रमशः 29 प्रतिशत तक और 5 प्रतिशत तक बढ़ी है। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि आयात 38 प्रतिशत तक बढ़े हैं। घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाया है।

- xi. यहां तक कि जब घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री में सुधार हुआ है, यह देखा जाएगा कि कुछ ग्राहकों को घरेलू उद्योग की बिक्री में तेजी से गिरावट आई है। बिक्री में ये गिरावटें इन ग्राहकों द्वारा खपत में गिरावट के कारण नहीं हैं। बिक्री में यह गिरावट इन ग्राहकों द्वारा आयातित सामग्री की खरीद के कारण है।
- xii. पाटित आयातों से बाजार में भारी दबाव बना है और घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बाजार हिस्सा खोया है।
- xiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पूरी क्षति अवधि में काफी गिरावट आई है। पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय ने लाभप्रदता की प्रवृत्ति की तरह वही प्रवृत्ति दर्शाई है।
- xiv. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी आधार वर्ष और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग बाजार में काफी कीमत न्यूनीकरण का सामना कर रहा है। कीमत न्यूनीकरण का परिणाम लाभ मानदंडों में भारी गिरावट है।
- xv. मालसूची जांच की अवधि में बढ़ी है। उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण अपनी संचित मालसूची का निपटान करने में असमर्थ है।
- xvi. याचिकाकर्ता अपनी बिक्री बनाए रखने में समर्थ रहा है क्योंकि वे अपनी कीमतों से समझौता करते हैं। अन्य उत्पादक की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
- xvii. क्षमता उपयोग, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी, निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है।
- xviii. उत्पादन, कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है और लाभ में उतार-चढ़ाव नहीं होता।
- xix. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव से घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास हुआ है और वह निवेश पर आय, लाभ, प्रति यूनिट नकद लाभ, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा में गिरती हुई प्रवृत्तियों से देखा जाता है।
- xx. निवल अचल परिसंपत्तियों और मजदूरी, दोनों में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। कार्यशील पूंजी 2015-16 तक कम होती रही है और फिर थोड़ी सी वृद्धि हुई परंतु आधार वर्ष से तुलना करने पर वह अब भी कम है।
- xxi. विचाराधीन उत्पाद, कॉटन लैंटर तथा पूर्ण पल्प दोनों से बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने जलवायु की स्थिति के आधार पर दोनों का प्रयोग किया। किसी भी समय कच्ची सामग्री की कमी नहीं रही है और याचिकाकर्ता को इस निमित्त कभी कोई क्षति नहीं हुई है।
- xxii. वास्तविक क्षति का खतरा है। निर्यातकों के पास अधिशेष क्षमताएं हैं और यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है तो आयात और अधिक होंगे।
- xxiii. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतें प्रत्येक देश के बाजार प्रभाव के आधार पर देश-देश में अलग-अलग हैं। याचिकाकर्ता की निर्यात कीमतें भारत में निर्यातों के लिए संबद्ध देशों की कीमतों से काफी अधिक हैं।

xxiv. घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करने के संबंध में कोई साधन नहीं है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़े आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग के निष्पादन में और हास दर्शाएंगे।

छ. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आयात पूर्ण दृष्टि से और तुलनात्मक दृष्टि से नहीं बढ़े हैं। कोई मात्रात्मक क्षति नहीं है और जो क्षति हुई है, उसका पूर्णतः संबद्ध देशों से आयातों से कोई सह संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता के निष्पादन में आयातों में वृद्धि से सुधार हुआ है।
- ii. आयात मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण हो रहे हैं।
- iii. मांग-खपत के संबंध में आयात विशेष रूप से थाइलैंड में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 4 प्रतिशत तक गिरावट आई है। जांच की अवधि में और वर्ष 2015-16 में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट अन्य नए भारतीय उत्पादकों के कारण है जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू किया है।
- iv. संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत से याचिकाकर्ता की निवल बिक्री वसूली प्रभावित नहीं हुई है और इस प्रकार कोई कीमत न्यूनीकरण/हास नहीं हो रहा है। 2015-16 से जांच की अवधि तक पहुँच कीमत में गिरावट के बावजूद याचिकाकर्ता की निवल बिक्री वसूली में उसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- v. मौखिक सुनवाई में याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उनका क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत है और वे निरंतर सामानों का उत्पादन करने में सक्षम हैं। घरेलू उद्योग के निष्पादन में सकारात्मक वृद्धि है। प्रपत्र-ज में दिए गए आंकड़े भिन्न हैं और प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों की परिशुद्धता की जांच करनी चाहिए।
- vi. बाजार सूचना के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षमता 11000 मी. टन प्रति वर्ष है जबकि संबद्ध सामानों के लिए मांग 13000 मी. टन प्रति वर्ष है। घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का 20-30 प्रतिशत निर्यात करता है। अतः केवल 8000 मी. टन प्रति वर्ष घरेलू बिक्री के लिए रह जाता है। विश्वसनीयता का अभाव है और यही कारण है कि ग्राहकों ने आयातों का विकल्प लिया है।
- vii. याचिकाकर्ता अपनी मालसूची का उपयोग करने में सक्षम रहे हैं और जांच की अवधि में अधिक बिक्री करने में सक्षम रहे हैं।
- viii. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता, उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में समर्थ रहा है और 70 प्रतिशत बाजार हिस्से पर उसका नियंत्रण है। क्षति का दावा नहीं पाया गया है।
- ix. निवल बिक्री वसूली जांच की अवधि में बिक्री लागत के अनुरूप है जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर आयात कीमतों का कोई प्रभाव नहीं है।
- x. निवल बिक्री वसूली और लाभ में पूरी क्षति अवधि में हो रही कीमत कटौती को ध्यान में न रखते हुए उतार-चढ़ाव होता रहा है। यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता लाभ कमाता रहा है और निवल बिक्री वसूली बनाए रखने में सक्षम रहा है।

- xi. घरेलू उद्योग की बिक्री पूरी क्षति की अवधि में निरंतर बढ़ती रही है। घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन संबद्ध आयातों को ध्यान में न रखते हुए लाभप्रद रहा है। याचिकाकर्ता की बिक्री पर यदि कोई प्रभाव है तो वह 2015-16 में विचाराधीन उत्पाद के बाजार में आने वाले अन्य नए उत्पादकों के कारण है न कि संबद्ध आयातों के कारण।
- xii. याचिकाकर्ता अपनी मालसूची का उपयोग करने में सक्षम रहा है और जांच की अवधि में अधिक बिक्री करने में सक्षम रहा है।
- xiii. घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या जांच की अवधि में और पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है।
- xiv. याचिकाकर्ताओं ने अपने क्षति विश्लेषण में नियोजित पूंजी पर आय और मजदूरी पर विश्वास किया है, परंतु उस संबंध में कोई आंकड़े देने में विफल रहे हैं।
- xv. नाइट्रस केमिकल्स इंडिया लि. (याचिकाकर्ता) डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार (एडीए) के अनुच्छेद 5.2 का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य देने में विफल रहा और इस प्रकार डीजीटीआर से अनुरोध है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को रद्द करें अथवा किसी संरक्षक उपाय के बिना वर्तमान जांच को रद्द करें।
- xvi. घरेलू उद्योग को क्षति स्वप्रभावित है और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विस्तार का कारण है।
- xvii. यह महत्वपूर्ण विस्तार विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की अपनी उत्पादन मात्रा 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 23 प्रतिशत तक और 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में 4 प्रतिशत की वृद्धि तक बढ़ाने के लिए उसकी शीर्ष क्षमता के क्रम में है।
- xviii. याचिकाकर्ता की उत्पादकता में 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 28 प्रतिशत तक की सकारात्मक वृद्धि महसूस की गई और उसके लिए वृद्धि 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में 5 प्रतिशत तक जारी रही। याचिकाकर्ता अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में सक्षम रहा है।
- xix. याचिकाकर्ता को क्षति उनके द्वारा किए गए विस्तार के कारण है। याचिकाकर्ता की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट यह दर्शाती है कि घरेलू बिक्री से राजस्व का हिस्सा पिछले तीन वर्षों में (2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017) में लगभग स्थिर रही है और इसके अतिरिक्त उसका कारोबार इन्हीं अवधियों में बढ़ा है।
- xx. घरेलू उद्योग की बिक्री पूरी क्षति अवधि में निरंतर बढ़ती रही है। घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन संबद्ध आयातों को ध्यान में न रखते हुए लाभप्रद रहा है। याचिकाकर्ता की बिक्री पर कोई प्रभाव यदि है, तो वह 2015-16 में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू बाजार में आने वाले अन्य नए उत्पादकों के कारण है न कि संबद्ध आयातों के कारण।
- xxi. याचिकाकर्ता जिस एक संयंत्र में प्रचालन करता है, वह विनियामक मुद्दों के कारण 2013 तक 5 वर्षों के लिए बंद किया गया था। यहां तक कि यद्यपि वह 2014 में पुनः शुरू किया गया था, तथापि, संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2017 तक प्रचालनात्मक हानियां महसूस कीं। यह भारी हानियों के कारण खंडनयोग्य नहीं है, उसे वास्तव में उसके संयंत्र के बंद होने के कारण हानि हुई है जो विचाराधीन उत्पाद के कारण नहीं मानी जा सकती।

- xxii. डीजीटीआर को 2016-17 में याचिकाकर्ता के लाभ एवं हानि खाते में प्रस्तुत विविध व्ययों की राशि में पर्याप्त वृद्धि संबंधी तथ्य की जांच करनी चाहिए जिसके लिए ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। यह 2015-16 और 2014-15 की तुलना में काफी अधिक राशि है जिसकी डीजीटीआर को कारणात्मकता के हित और इस जांच में कारक न होने के लिए सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।
- xxiii. याचिकाकर्ता को क्षति संबद्ध आयातों के बजाए वैश्विक कीमत प्रवृत्तियों के कारण हुई है, जैसा कि देखा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने उन बाजारों को समान कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात किया है जहां कीमतों का ह्रास करने तथा कीमतों की कटौती करने के लिए तथाकथित कोई पाटित आयात नहीं हैं।
- xxiv. कॉटन लिंटर्स का उत्पादन/आपूर्ति, जो कि एक कच्ची सामग्री है, जलवायु की स्थितियों से प्रमुख रूप से प्रभावित है और परिणामस्वरूप उससे याचिकाकर्ता की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।
- xxv. कीमत प्रभाव विश्लेषण की किस्म दर किस्म तुलना जांच के सही और उचित परिणाम तक पहुँचने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इंडोनेशिया के विरुद्ध पाटनरोधी उपाय लगाए जाने (डीएस 480) – ईयू की पैनल रिपोर्ट में डब्ल्यूटीओ में हाल का एक निर्णय है कि कीमत प्रभाव विश्लेषण, जहां किस्म दर किस्म कीमत विश्लेषण की आवश्यकता हो, तुलनीय आधार पर किया जाना होता है।
- xxvi. भारत में इंडोनेशिया से निर्यात घरेलू उद्योग का पूरक है और निचले उद्योग की सहायता करता है।

छ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसरण में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।
51. जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की यथार्थता का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के निष्कर्ष सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।
52. मांग-आपूर्ति अंतर के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग-आपूर्ति अंतर विद्यमान है, विदेशी उत्पादक निश्चय ही उचित कीमत पर उत्पाद लाकर देश में इस अंतर को पूरा कर सकते हैं। मांग-आपूर्ति अंतर उत्पाद के पाटन का समर्थन नहीं करता।
53. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को नोट किया है कि सस्ते आयातों के कारण घरेलू उद्योग में उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या द्वारा उत्पाद की मांग में महत्वपूर्ण हिस्से को गंवा दिया है।
54. क्षति और कारणात्मक संबंधों के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की जांच की गई और उनका निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:
55. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा मात्रा और कीमत प्रभाव, दोनों की जांच द्वारा क्षति की जांच किया जाना अनिवार्य है। क्षति के निर्धारण में दोनों की उद्देश्यपरक जांच शामिल है (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार की कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना

अनिवार्य है कि क्या पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, चाहे वह कुल रूप में हो या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अनिवार्य है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में कमी करता अथवा कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण करता जो अन्यथा रूप से घटित हुई होती। जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

56. प्राधिकारी ने सभी क्षति मानकों पर विचार किया है और तत्पश्चात सभी मानकों की सामूहिक और संचित जांच के आधार पर निष्कर्ष दिया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके उत्तरों/अनुरोधों और प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षति मानकों की उद्देश्यपरक जांच की है।

छ. 4 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

(क) भारत में मांग/खपत

57. भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या खपत को सभी स्रोतों से भारतीय उत्पादकों और आयातों की घरेलू बिक्रियों के योग द्वारा संकलित किया गया है:

मांग	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	1,396	1,273	1,606	1,818
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	600	600	1,140	1,177
संबद्ध देशों से आयात					
थाइलैंड	मी. टन	1,919	1,899	1,828	2,703
ब्राजील	मी. टन	511	884	980	761
इंडोनेशिया	मी. टन	-	-	62	517
संबद्ध देश	मी. टन	2,430	2,783	2,870	3,981
अन्य	मी. टन	945	817	640	377
कुल मांग	मी. टन	5,371	5,473	6,256	7,353

58. यह नोट किया गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी है।

(ख) आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

59. प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में या तो उत्पादन या खपत के सापेक्ष अथवा कुल रूप में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथ्यात्मक वृद्धि निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
मात्रा					
थाइलैंड	मी. टन	1,919	1,899	1,828	2,703
ब्राजील	मी. टन	511	884	980	761
इंडोनेशिया	मी. टन	-	-	62	517
संबद्ध देश	मी. टन	2,430	2,783	2,870	3,981
अन्य	मी. टन	945	817	640	377
कुल आयात	मी. टन	3,375	3,600	3,510	4,359
के संबंध में संबद्ध देश को आयात					
भारतीय उत्पादन	%	95	91	78	97
मांग	%	45	51	46	54
कुल आयात	%	72	77	82	91
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	174	219	179	219

60. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध देशों से आयातों में कुल रूप में वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष के बाद से जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में 37 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों से आयातों में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ख. क्षति की अवधि में कुल आयातों के संबंध में आयातों का हिस्सा 72 प्रतिशत से 91 प्रतिशत बढ़ा है। इस प्रकार, पूरी क्षति की अवधि के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
- ग. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू बिक्रियों के संबंध में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि घरेलू बिक्रियों के संबंध में आयातों में आधार वर्ष के बाद से जांच की अवधि में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

छ. 5 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विश्लेषण किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों को प्रभाव से कीमतों में ह्रास हुआ है अथवा कीमतों की वृद्धि पर नियंत्रण हुआ है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुआ होता। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत में वृद्धि, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की संबद्ध देश से आयातों की पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

(क) कीमत कटौती

62. व्यापार के समान स्तर पर, सभी छूटों और रियायतों को घटाकर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पाद के पहुँच मूल्य के बीच तुलना की गई है। प्राधिकारी ने आयातों की पहुँच कीमत की संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना की है।

कीमत कटौती - भारत	यूनिट	थाइलैंड	ब्राजील	इंडोनेशिया	संबद्ध देश (कुल)
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	173	168	165	171
निवल बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	15-25	20-30	10-20

63. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भिन्न थी। इस प्रकार, यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे थे।

(ख) कम कीमत पर बिक्री

64. प्राधिकारी ने कम कीमत पर बिक्री की घरेलू उद्योग के एनआईपी के साथ आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना द्वारा भी जांच की है।

विवरण	यूओएम	थाइलैंड	ब्राजील	इंडोनेशिया	संबद्ध देश
क्षति रहित कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
पहुँच कीमत	रु./कि. ग्रा.	173	168	165	171
कम कीमत पर बिक्री	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज (%)	20-30	20-30	20-30	20-30

65. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम थी। प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

(ग) पाटित आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव

66. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के आयातों के पहुँच मूल्य के साथ यह निर्धारित करने के लिए तुलना की गई है कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे थे, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	89	95
बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	88	92

पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	111	90

67. यह देखा गया है कि पहुँच कीमत बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से कम है। जांच की अवधि में बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में गिरावट आदि है। तथापि, यह नोट किया गया है कि बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में आई गिरावट की तुलना में अधिक है। इसलिए, आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में हास कर रहे थे।

ज. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानकों की जांच

68. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और आंकड़ों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता में वास्तविक और संभावित गिरावट, निवेशों अथवा क्षमता के उपयोग पर वापिसी, घरेलू उद्योग कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरियों, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानकों का एतद्वारा नीचे विश्लेषण किया गया है।

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा

69. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	158	182
उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	127	134	218
उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	126	130	150
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	81	84	121
घरेलू बिक्री विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	115	130

70. यह देखा गया है कि:

- क. याचिकाकर्ता ने क्षति की अवधि में अपनी क्षमता में वृद्धि की है। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि क्षमता में वृद्धि भातर में संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप की गई थी।

- ख. उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- ग. आधार वर्ष के बाद से जबकि जांच की अवधि में उत्पाद की मांग 37 प्रतिशत बढ़ी है, घरेलू उद्योग की बिक्रियां केवल 30 प्रतिशत बढ़ी है। जहां याचिकाकर्ता अन्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने में सक्षम था, वही याचिकाकर्ता मांग में वृद्धि के समानुपात में उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।
- घ. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग कीमतों पर समझौता करने के द्वारा बिक्रियों में वृद्धि करने में सक्षम है, जिसके परिणामस्वरूप लाभों में गिरावट आई है।

(क) मांग में बाजार हिस्सा

71. भारतीय मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
याचिकाकर्ता का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	90	99	95
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	163	143
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	101	120
थाइलैंड	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	82	103
ब्राजील	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	170	165	109
इंडोनेशिया	%	-	-	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	100	712
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	85	58	29
कुल मांग	%	100	100	100	100

72. यह देखा गया है कि भारतीय मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से ने मामूली गिरावट दर्शाई है जबकि क्षति की अवधि में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। असंबद्ध देशों के हिस्से और आयात में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग इसका कोई लाभ उठाने में सक्षम नहीं है उन कीमतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर तीसरे देशों के आयातों की तुलना में संबद्ध देशों के आयातों की बिक्री की गई है।

(ख) मालसूचियां

73. घरेलू उद्योग की औसत मालसूचियों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	146	158	138

74. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के बाद से घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में वृद्धि हुई है। तथापि, कुल रूप में न तो मालसूचियों का स्तर चिन्ताजनक रूप से उच्च है न ही घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि इस उद्योग में मालसूची के स्तर निर्धारित मानदंडों से उच्च थे।

(ग) लाभ, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह

75. लाभप्रदता, पीबीआईटी, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री की लागत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	89	94
बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	88	92
लाभ/(हानि)	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(429)	(104)	(158)
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(392)	(120)	(206)
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(589)	(155)	(310)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(406)	188	30
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(533)	(99)	(234)

76. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2015-16 तक गिरावट आई और उसके पश्चात जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई। हालांकि, बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट की तुलना में अधिक थी।
- घरेलू उद्योग ने पूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानियों का सामना किया है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियों में वृद्धि हुई है।
- क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के नकद लाभों में भी गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के निष्पादन में नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में ह्रास हुआ है।

77. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि लाभों, नकदी लाभों और निवेशों पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास हुआ है।

(घ) रोजगार और मजदूरी

78. रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता और वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	107	114
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	119	129	127
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	126	130	150
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	121	131

79. यह देखा गया है कि रोजगार, मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ड) वृद्धि

80. नीचे दी गई सारणी दर्शाती है कि विभिन्न मानकों के रूप में कंपनी की वृद्धि निम्नानुसार थी:

पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	26	3	15
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	(9)	26	13
लाभ	%	-	(292)	69	(72)
नकद लाभ	%	-	(506)	146	(84)
घरेलू बिक्री कीमत	%	-	(9)	(3)	4
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	(14)	14	(5)

81. यह नोट किया जाता है कि लाभों, नकदी लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और बाजार हिस्से एवं मालसूचियों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक थी जबकि उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा और घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में वृद्धि सकारात्मक थी।

(च) पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता

82. याचिकाकर्ता ने कहा है कि नए निवेश जुटाने की क्षमता उत्पाद के पाटन से प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि निवेश संबंधी निर्णय दीर्घावधिक निर्णय है और विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग पर विचार करते हुए लिए जाते हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की दीर्घावधिक व्यवहार्यता सुदृढ़ लाभप्रद व्यापार पर निर्भर करती है।

(छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

83. याचिकाकर्ता ने कहा है कि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम कीमत पर किए जा रहे हैं। चूंकि, बाजार में प्रतिस्पर्द्धा मुख्य रूप से घरेलू उद्योग और आयातों के बीच है और इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रयोक्ता घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच तुलना के बाद उत्पाद का क्रय कर रहे हैं। यह आयात कीमत है जो बिक्री कीमतों में गिरावट और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कीमत मानकों में गिरावट के लिए उत्तरदायी है।

(झ) क्षति संबंधी जांच परिणाम

84. इसलिए यह देखा गया है कि कुल रूप में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है। इसलिए, आयात कुल रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत, दोनों के संबंध में बढ़े हैं। पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग पाटित आयातों का कम कीमत पर बिक्री का महत्वपूर्ण रूप से सामना कर रहा है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन काफी महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि बाजार हिस्से, लाभों, नकद लाभों और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों का विपरीत प्रभाव पड़ा है। जबकि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग क्षति अवधि में नहीं है और वहीं इसकी बिक्री मात्राओं और बाजार हिस्से में मांग में वृद्धि के समानुपात में वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने निर्णय दिया है कि घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है।

(ञ) क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

85. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षति रहित कीमत की, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, की संबद्ध देशों से प्रत्येक सहयोगी निर्यातक के लिए आयातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई है और क्षति मार्जिन को एक भारांशित औसत आधार पर निर्धारित किया गया है। जहां तक शेष श्रेणी का संबंध है, एनआईपी की आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

क्षति मार्जिन

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातक	देश	एनआईपी	पहुँच	क्षति मार्जिन		
			र./कि. ग्रा.	र./कि. ग्रा.	र./कि. ग्रा.	%	रेंज
1	नाइट्रो केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड/नोबेल एनसी कं. लि.	थाइलैंड	***	***	***	***	15-25
2	क्रम सं. 1 को छोड़कर कोई अन्य	थाइलैंड	***	***	***	***	35-45
3	पीटी इंटी सेलुलसटामा/पीटी इंडोसेरा उतामा प्रेसिसी	इंडोनेशिया	***	***	***	***	20-30
4	क्रम सं. 3 को छोड़कर कोई अन्य	इंडोनेशिया	***	***	***	***	30-40
5	सभी उत्पादक	ब्राजील	***	***	***	***	20-30

ट. वस्तुपरक क्षति का खतरा

86. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि आयातों से घरेलू उद्योग को वस्तुपरक क्षति होने का खतरा हो रहा है। प्राधिकारी ने वस्तुपरक क्षति के खतरे के संबंध में भी विभिन्न मापदंडों की जांच की है:

- आयातों में बढ़ोत्तरी:** संबद्ध देशों से आयातों में पूर्णतः तथा उत्पादन और खपत के संदर्भ में बढ़ोत्तरी हुई है। यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में कुल आयातों के 91 प्रतिशत आयात शामिल हैं। पूर्ववर्ती देश की तुलना में जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की बढ़ोत्तरी की पर्याप्त दर भारी मात्रा में बढ़े हुए आयात के खतरे को दर्शाती है। याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि जांच की अवधि के बाद उत्पाद के आयातों में और बढ़ोत्तरी हुई।

- ii. **अधिशेष क्षमता:** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाइलैंड की क्षमता प्रति वर्ष 40,000 मी. टन है, जबकि उनकी अनुमानित घरेलू मांग लगभग 4,000 मी. टन है। अतः थाइलैंड के उपलब्ध अधिशेष क्षमता काफी है और यह लगभग 36,000 मी. टन प्रति वर्ष है। इंडोनेशिया का बाजार बहुत छोटा है और उन्होंने इंडोनेशिया में एक संयंत्र की स्थापना की है, और क्षमता 4,000 मी. टन है। यह इस बात को दर्शाता है कि इंडोनेशिया के पास आसानी से निपटान करने लायक पर्याप्त क्षमता है। ब्राजील के पास उपलब्ध कुल क्षमता (याचिकाकर्ता के अनुसार) 38,000 मी. टन प्रति वर्ष है और खपत 7000-8000 मी. टन प्रति वर्ष है। निर्यातक की ऐसी अधिशेष क्षमता किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता के अध्येक्षी भारतीय बाजारों में उसकी बढ़ती हुई मांग को स्वीकार करते हुए बढ़ते हुए संभावित निर्यातों को दर्शाती है।
- iii. **मालसूचियां:** निर्यातकों के प्रत्युत्तरों में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मालसूचियों के संबंध में प्राधिकारी ने व्यौरों की जांच की है और यह देखा गया है कि मालसूचियों के स्तर में कमी हुई है।

87. सूचित की गई सूचना की जांच यह दर्शाती है कि पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। उपरोक्त अभिज्ञात कारक आगे क्षति होने के खतरा को साफ-साफ दर्शाते हैं।

ठ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

88. यह भी जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य निम्नलिखित मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। निम्नानुसार यह नोट किया है:

(क) अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

89. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया है कि चीन को छोड़कर अन्य देशों से आयात नगण्य हैं और इससे घरेलू उद्योग के लिए क्षति होने का दावा नहीं कर सकता है। यह भी देखा गया है कि जबकि कुल आयातों में संबद्ध देशों का हिस्सा 72 प्रतिशत (2013-14) से बढ़कर 91 प्रतिशत (जांच की अवधि) हुआ, परन्तु गैर-संबद्ध देशों के हिस्से में आनुपातिक रूप से कमी हुई। गैर-संबद्ध देशों के मामले में न्यूनतम से कम सीमाओं के बाद आयातों के बारे में ताइवान (2013-14 और 2014-15 में) तथा चीन से सूचना प्राप्त हुई थी। ताइवान से आयातों में जांच की अवधि के दौरान न्यूनतम से कम सीमा तक कमी हुई। जबकि चीन से आयात जांच की अवधि के दौरान न्यूनतम से कम सीमा के बाद हुए, चीन से आयातों की मात्रा भारत में पूर्णतः और कुल आयात, उत्पादन और खपत दोनों की दृष्टि से क्षति की अवधि के दौरान धीरे-धीरे गिरावट आई। प्रचलित सीमा शुल्क को जोड़ने के बाद चीन से आयात कीमत संबद्ध देशों के मुकाबले काफी अधिक थी। इसके अलावा, क्षति की अवधि के दौरान चीन से आयातों का पहुँच मूल्य संबद्ध देशों के मुकाबले अधिक था और उससे घरेलू उद्योगों को क्षति नहीं हो सकती थी।

(ख) मांग में कमी और खपत के पैटर्न में बदलाव

90. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग/स्पष्ट खपत में बढोत्तरी हुई है और इस तरह से मांग की कमी क्षति पहुँचाने का कारक नहीं हो सकती है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

91. संबद्ध उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है।

(घ) प्रतिस्पर्द्धी की शर्तों और व्यापार प्रतिबंध संबंधी कार्य

92. व्यापार संबंधी ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक कार्य नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

93. केवल उनके घरेलू कार्यों को ही ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी के द्वारा क्षति विश्लेषण किया गया है। इसीलिए निर्यात निष्पादन से वर्तमान क्षति विश्लेषण पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(च) घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन

94. घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के उत्पादन के बारे में प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी के द्वारा विचार की गई सूचना विचाराधीन उत्पाद के बारे में ही है।

(छ) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उसी प्रवृत्ति को अपनाया है जो उत्पादन के बारे में है और यह बढोत्तरी को दर्शाती है। उत्पादन में कमी होना घरेलू उद्योग में क्षति का कारण नहीं है।

(ज) कारणात्मक संपर्क दर्शाने वाले मापदंड

96. पाटित आयातों और घरेलू उद्योगों को क्षति के बीच में कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित आधार पर सुनिश्चित किए जाते हैं:

- i. संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हैं;
- ii. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, परिणामतः घरेलू उद्योग ने लागत से कहीं अधिक कमी से अभी कीमतों में कमी की है।
- iii. कीमत में कटौती होने की वजह घरेलू उद्योग के सामने कीमत दबाव के कारण घरेलू उद्योग के लाभों, नकद लाभों और निवेश पर आय में कमी हुई है।
- iv. जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में काफी बढोत्तरी हुई। यद्यपि आयातों के बाजार हिस्से में बढोत्तरी हुई और घरेलू उद्योग के उस हिस्से में कमी हुई। अतः कम कीमत के बढे हुए आयातों को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई गिरावट से जोड़ा है।

ड. प्रयोक्ता उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन, सामान्य तौर पर, पाटन के अनुचित व्यापार कार्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और स्पष्ट प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों/क्षेत्र से आयातों को किसी प्रकार से सीमित नहीं करना होगा और इसलिए उपभोक्ताओं के उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेंगे।
98. यह स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणामतः इस उत्पाद के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव हो सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में स्पष्ट प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेष तौर पर यदि पाटनरोधी शुल्क को लगाना घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए एक आवश्यक राशि तक सीमित किया हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन कार्यों से हुए अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेगी।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटन के बाद निवेदन**ढ. 1 घरेलू उद्योग के विचार**

99. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निवेदन किया:

- i. अनिवार्य तथ्यों में क्षति संबंधी मापदंडों पर निष्कर्ष तथ्य के विषयों पर निष्कर्ष, उत्पाद, समान वस्तु और घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र, पाटन और पाटन मार्जिन शामिल है। इनके बारे में निर्णय को प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करना जरूरी होता है।
- ii. घरेलू उद्योग के बड़े-बड़े उपभोक्ताओं ने निर्यातकों के द्वारा प्रदान की गई पाटित कीमतों की वजह से आयात करने को तरजीह दी थी। याचिकाकर्ता ने क्षमताओं में बढ़ोत्तरी की है और बाजार में अपने उत्पाद की मांग बढ़ाने के लिए कार्य करना जारी रखा। मांग में इस परिणामी बढ़ोत्तरी को निर्यातकों ने आयातों के बाजार हिस्से में हुई बढ़ोत्तरी के रूप में लिया था।
- iii. संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से की अलग-अलग जांच करनी चाहिए क्योंकि उनमें से एक उत्पादक ने अभी हाल ही में बाजार में प्रवेश किया है।
- iv. थाइलैंड की सीआईएफ कीमतें, इंडोनेशिया और ब्राजील की कीमतों से काफी अधिक हैं, तथापि, वे सही कीमतों को नहीं दर्शाते हैं। थाइलैंड से एनसीआई और एनएनसी के द्वारा काफी "छूट" प्रदान की जाती है।
- v. भारत के सम्पूर्ण आयातों में से 41 प्रतिशत (विचाराधीन उत्पाद के 1662 मी. टन) आयात एक प्रयोक्ता अर्थात् एसडी पेट्स द्वारा किया जाता था और उसने याचिकाकर्ता को ऐसी छूट के बराबर छूट देने के लिए अनुरोध किया है जो आयातित सामग्री के लिए प्रदान की जा रही है। ग्राहक ने यह साफ-साफ कहा है कि सीआईएफ कीमतों पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन पर भारी छूट दी जा रही है। इसके प्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
- vi. हुबरे और सीजवर्क सहित जांच की अवधि के दौरान अन्य बड़े आयातकर्ता बाजार सूचना के अनुसार बीजक के बाद मात्रा संबंधी छूट प्राप्त करते हैं। ऐसी छूट आयात आंकड़े और आयात कीमत को नहीं दर्शाते हैं। यदि अपेक्षित हो तो याचिकाकर्ता शपथ-पत्र पर एक विवरण देगा।

- vii. लगभग 70 प्रतिशत आयातों पर थाइलैंड विशेष छूट प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा वह इंडोनेशिया और ब्राजील की कीमतों की तुलना में अपनी आयात कीमतें काफी कम रख रहे हैं।
- viii. अन्य देशों से आयातों की मात्रा थाइलैंड के आयातों की मात्रा से काफी कम है। जहां तक इंडोनेशिया का संबंध है, उनकी आयात कीमत थाइलैंड से कम है, इंडोनेशिया से आयात में वृद्धि काफी अधिक है। इंडोनेशिया से आयात वर्ष 2015-16 में ही शुरू हुए थे और जांच की अवधि के दौरान मात्रा में लगभग 8-9 गुना बढ़ोत्तरी हुई। अतः थाइलैंड की तुलना में इंडोनेशिया के उत्पादकों ने आयात कीमत में काफी कमी की है, यह तथ्य थाइलैंड से हुए आयात की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी को पूर्णतः दर्शाता है।
- ix. याचिकाकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण के बारे में प्राधिकारी ने विचार किया है और यह नोट किया है कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने याचिकाकर्ता को संयंत्र बंदी का नोटिस जारी किया था; तथापि, याचिकाकर्ता ने नोटिस जारी होने के शीघ्र बाद बोर्ड के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया और संयंत्र कभी बंद नहीं हुआ।
- x. याचिकाकर्ता ने देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं में बढ़ोत्तरी की। तथापि, इस अवधि के दौरान मांग में 2,897 मी. टन की बढ़ोत्तरी होने पर भी याचिकाकर्ता अपनी विक्रियों को आनुपातिक रूप से बढ़ा नहीं सका था।
- xi. मांग में हुई बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने वर्ष 2014-15 और जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में बढ़ोत्तरी की है। तथापि, घरेलू उद्योग मांग में हुई बढ़ोत्तरी के अनुपात में अपने उत्पादन और विक्री में बढ़ोत्तरी करने में असमर्थ रहा था।
- xii. वर्ष 2015-16 तक उत्पादन और क्षमता उपयोग में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके बाद, यद्यपि, उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई, परंतु जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट हुई। केवल उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई, क्योंकि याचिकाकर्ता निर्यातों को बढ़ा सका था, अन्यथा याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त मालसूची का सामना किया।
- xiii. विक्रियों में केवल इस वजह से बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने उत्पाद की विक्री करने के लिए विक्री कीमत के बारे में समझौता किया था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग मांग में हुई बढ़ोत्तरी के अनुपात में उत्पाद की विक्री नहीं कर सका है।
- xiv. घरेलू उद्योग की विक्रियों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस तथ्य को विभिन्न ग्राहकों की विक्री पद्धति से तत्काल स्थापित किया जाता है। घरेलू उद्योग की समग्र विक्रियों में सुधार होने पर भी यह देखा जाएगा कि कुछ ग्राहकों के लिए घरेलू उद्योग की विक्रियों में धीरे-धीरे गिरावट हुई। विक्रियों में ये गिरावट इन उपभोक्ताओं की खपत में कमी होने की वजह से नहीं है। विक्रियों में ये गिरावट इन उपभोक्ताओं की आयातित सामग्री की प्राप्ति के वजह से हुई है।
- xv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2015-16 तक बढ़ोत्तरी हुई है और फिर जांच की अवधि के दौरान गिरावट हुई। बाजार हिस्से की हानि का कारण संबद्ध देशों से आयातों का पाटन है। वर्ष 2015-16 तक बाजार हिस्से में बढ़ोत्तरी होने और विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमताओं में बढ़ोत्तरी होने से ऐसी कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान कमी होनी चाहिए।

- xvi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, पीवीआईटी और नियोजित पूंजी पर लाभ में वर्ष 2014-15 में गिरावट हुई। तथापि, बाद में वर्ष 2015-16 में हानियों में कमी हुई। देश में उत्पाद के पाटन से जांच की अवधि में हानियों में काफी बढ़ोत्तरी हुई।
- xvii. घरेलू उद्योग के सामने पर्याप्त कीमत दबाव से नकद लाभ मापदंडों में अत्यधिक कमी हुई है।
- xviii. क्षति की अवधि में मालसूचियों में बढ़ोत्तरी हुई है। पाटित आयातों की वजह से उद्योग अपनी संचित मालसूचियों का निपटारा नहीं कर सका है।
- xix. क्षमता उपयोग, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीवीआईटी और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक रहा है। क्षमता में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए विकास ज्यादा बेहतर होना चाहिए।
- xx. संबद्ध देशों से मांग पर्याप्त बढ़ोत्तरी को दिखा रही है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने का कारक नहीं हो सकता है। उपभोक्ता आयात कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग के साथ कीमतों के बारे में समझौता कर रहे हैं। अतः घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत है।
- xxi. पाटित आयातों के अलावा, निर्यात निष्पादन, प्रौद्योगिकी में बदलाव, कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन, प्रतिस्पर्धा की शर्तें, अथवा खपत पद्धति में बदलाव जैसे किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।
- xxii. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। परिणामतः आयात की कम कीमतें घरेलू उद्योग को उत्पादन की लागत के बारे में उनकी समतुल्य कीमतों को रोक रही है।
- xxiii. कीमतों में कटौती होने से बिक्री संबंधी कीमतों में कमी हुई है। एक प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, घरेलू उद्योग को नकद लाभों में कमी हो रही है और उसकी हानियां बढ़ीं तथा निवेश पर नकारात्मक आय हुई।
- xxiv. यद्यपि, घरेलू उद्योग उप इष्टतम कीमतें प्रदान कर रहा है, परंतु यह अपना बाजार हिस्सा खो रहा है। याचिकाकर्ता ने क्षति की अवधि के दौरान या तो पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से अपने प्रमुख ग्राहकों की बिक्रियां नहीं की हैं।
- xxv. अमेरिकी डॉलर/मी. टन में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क (शुल्क का नियत स्वरूप) की निश्चित मात्रा के रूप में ही पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। कोई तंत्र न होने से आयात कीमत की जांच करने के लिए पत्तन प्राधिकारियों के लिए यह न तो व्यवहार्य है अथवा व्यावहारिक नहीं है। कानून में प्राधिकारी को अनुरोध किए। स्वरूप और तरीके से शुल्क लगाने के लिए अनुमति देता है।
- xxvi. शुल्क इस तरीके से लगाना चाहिए जिससे यह व्यर्थ न हो जाए। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि यदि शुल्क ठीक से नहीं लगाया जाता है तो इनको रोका जाता है। उपायों के गलत स्वरूप के आधार पर सेसटेट निर्णयों के प्राधिकार के आदेश से संशोधित किया है।
- xxvii. रुपए में काफी गिरावट हुई है और इसलिए निश्चित शुल्क कृपया अमेरिकी शुल्क में व्यक्त किया जा सकता है। चीन से मेटकोक मामले में सेसटेट के निर्णय में विवेकी रूप से शामिल करके इसका समर्थन भी किया जाता है।

ढ. 2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निवेदन

100. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए थे:

- i. पीटी आईयूपी ने यह तर्क दिया कि प्राधिकारी के द्वारा तैयार किए गए पीसीएन चिपचिपाहट (विस्कोसिटी) की उपेक्षा करती है जो एक महत्वपूर्ण निर्धारक औद्योगिक नाइट्रोसेलुलोस है। विस्कोसिटी लागत को प्रभावित करती है और कीमत की तुलना को प्रभावित करती है। अलग-अलग प्रयोक्ताओं को अलग-अलग विस्कोसिटी की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन सामग्री, फार्म पाउडर/घोल और विस्कोसिटी का उपयोग करते हुए ईक्यूआर में पीसीएन तैयार की गई थी। इन गुणों के बिना कोई भी पीसीएन अपूर्ण और गलत है।
- ii. सभी तीनों कारकों (5 प्रतिशत लाभ सहित) के आधार पर मार्जिन की गणना उपलब्ध कराई गई है। किसी एक गुण को हटा करके किसी गणना का परिणाम अनुचित है।
- iii. एक अकेले विचाराधीन उत्पाद के रूप में नाइट्रोसेलुलेस पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना की है। एक अकेले उत्पाद के रूप में सभी उत्तरों पर विचार करते हुए पीटी आईयूपी के लिए गणना किया गया मार्जिन किसी पाटन को वस्तुतः नहीं दर्शाता है।
- iv. जबकि पाटन मार्जिन की गणना करने में घरेलू बिक्री कीमत के बारे में प्रत्येक श्रेणी यानि एचएनपी, एचएनएस और एलएनपी के लिए भारित औसत के रूप में विचार किया गया है, निर्यात बिक्री कीमत के बारे में इसी आधार पर विचार नहीं किया गया है। प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर में पीसीएन के अनुसार इस विवरण में निर्यात बिक्री कीमत पर पीसीएन-वार विचार किया गया है।
- v. क्षति अथवा खतरे का कोई प्रमाण नहीं है, जैसा कि वृत्तांत 69 में दी गई सारणी से देखा जा सकता है। क्षति का कोई दावा वृष्टिपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता की उत्पादन क्षमता में जांच की अवधि के दौरान 82 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जो विकास की उच्चतम स्थिति है। क्षमता में बढ़ोत्तरी को उसके उत्पादन के अविश्वसनीय निष्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की मात्रा के साथ देखा जा सकता है। इस प्रकार कोई वस्तुगत क्षति नहीं हुई है।
- vi. जांच की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के लेखापरीक्षण किए गए वित्तीय विवरण स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है। चूंकि, कंपनी के जोखिम संबंधी खतरों की चेतावनी देने के तत्व बहुत ही कम हैं (वित्तीय विवरण 2016-17), इसीलिए कंपनी ने अपनी लाभप्रदता में सुधार किया है और कंपनी को कोई वित्तीय कठिनाई नहीं थी। इस बात को दर्शाते हुए कंपनी एसोसिएट में काफी राशि का निवेश कर सकी। वास्तव में इसने दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16) में लाभांश घोषित किया था।
- vii. याचिकाकर्ता के लाभ सहित गिरावट की कुछ प्रवृत्ति का इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयात से कोई लेना-देना नहीं था जिससे भारत में कुल आयात अथवा कुल मांग की अपर्याप्त मात्रा हुई। यदि याचिकाकर्ता क्षति के अपने दावे अथवा क्षति की चेतावनी के बारे में आग्रह करता है तो इससे उसकी क्षमता का अत्यधिक विस्तार होगा।
- viii. याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है और उसका निष्पादन क्षति की अवधि के दौरान विशेष रूप से अच्छा था। जांच को तत्काल समाप्त करने के लिए डीजीटीआर से अनुरोध है।

- ix. याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह परिभाषा का पालन करने में असमर्थ रहता है। याचिकाकर्ता की आरओसी तलाश यह दिखाती है कि रामदुरई मन्नाचन्नलुर राजाराम (आर. एम. राजाराम) 7 जनवरी, 2001 से 01 अप्रैल, 2014 तक एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति थे। आर. एम. राजाराम 7 जनवरी, 2001 से 01 अप्रैल, 2014 तक क्षति की गणना करने के लिए जांच की अवधि के एक वर्ष सहित जांच के जाने-माने आयातकों के साथ निदेशक भी थे।
- x. निर्यात किए गए उत्पादों और घरेलू उत्पादन की गुणवत्ता में काफी अंतर है। याचिकाकर्ता का उत्पाद रेशेदार किस्म का है जो निर्यातकों के द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद से काफी अलग है।
- xi. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर हितवद्ध पक्षकारों को अनुदेश जारी किए थे जिनमें उनसे अनुरोध किया गया था कि उन्हें गोपनीयता के ऐसे विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देनी थी जिनका निर्यातकों के द्वारा विधिवत पालन करना था। तथापि, अत्यधिक गोपनीयता के बारे में याचिकाकर्ताओं के दावे वैध नहीं थे।
- xii. निर्यातकों ने याचिकाकर्ताओं के गोपनीयता के दावों से संबंधित मुद्दे भी उठाए थे और यह स्पष्टीकरण भी मांगे गए हैं कि क्या निर्यातकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को याचिकाकर्ताओं के समक्ष रखा जाए, और सार्वजनिक फाइल एवं प्रकटन विवरण में उपर्युक्त व्यौरे रखने चाहिए।
- xiii. प्राधिकारी ने यह पाया है कि संयंत्र बंद नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पीसीबी के निर्देशों का पालन किया था। तथापि, याचिकाकर्ता के द्वारा इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था और इस बारे में हितवद्ध पक्षकारों के द्वारा बताने के बाद ही प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी। यह याचिकाकर्ताओं की साख और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है।
- xiv. इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपेक्षाओं का पालन न करने से लागत में बढ़ोत्तरी हुई अथवा किसी अन्य किस्म की आत्म क्षति हुई।
- xv. निर्यातक इस बात को नकारते हैं कि थाइलैंड द्वारा उठाए गए कदम नॉन टैरिफ बैरियर है। यह एक नीतिगत निर्णय है। किसी अन्य सदस्य राष्ट्र के द्वारा डब्ल्यूटीओ के लिए लिया जा सकता है। थाइलैंड के निर्यातों को छोड़कर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता के पास सामर्थ्य अथवा मालसूची नहीं होती है।
- xvi. प्रयोक्ता उद्योग के जनहित के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों से घरेलू उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर सकेगा क्योंकि क्षति की अवधि के प्रारंभ से ही विनिर्माण की प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और प्रचालनात्मक दक्षता के संबंध में मुद्दे रहे हैं।
- xvii. यह प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं कि थाइलैंड में घरेलू कीमतें विकृत हो गई हैं, इसीलिए सामान्य कीमत की गणना करने के लिए या तो तीसरे देश की बिक्री अथवा लागत (5 प्रतिशत लाभ सहित) को ध्यान में रखा गया है। बार-बार किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी के द्वारा निरस्त कर दिया गया और इसके लिए कोई कारण नहीं दिए गए। प्रकटन में अनुरोधों को भी स्वीकार नहीं किया गया। स्वाभाविक न्याय के हित में अनुरोधों और कारणों का प्रकटन विवरण में उल्लेख करना चाहिए।
- xviii. विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने के स्रोतों के बीच में उन्मुक्त प्रतिस्पर्द्धा के अभाव में थाइलैंड में बिक्री कीमतें असाधारण रूप से अधिक हैं। चूंकि, आयातों को बाजार में उन्मुक्त रूप से प्रवेश करने से अप्रत्यक्ष रूप से रोका जाता है, इसलिए सीमित आपूर्ति की वजह से कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। इससे एक ऐसा अकेला

बाजार हो गया जहां पर कीमत विकृत हो गई है और इसीलिए व्यापार की सामान्य अवधि में कोई विकृति नहीं हुई है।

- xix. यह जांच की जा सकती है कि कीमतें विकृत हो गई हैं क्योंकि थाइलैंड के निर्यातकों की कीमतें इंडोनेशिया के सहयोगी उत्पादकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य से काफी अधिक हैं। थाइलैंड में निर्यातकों की कीमत की अन्य देशों के निर्यातकों की कीमत से काफी अधिक है। निर्यातकों ने पूर्ण समायोजनों और अपने-अपने संबंधित व्यवस्थाओं से बैक-अप के साथ भारत के अलावा, निर्यात के अन्य तीन उच्च गंतव्य स्थलों के लिए अपनी कीमतों का ब्यौरा विशेष रूप से दायर किया है।
- xx. चूंकि, प्राधिकारी ने निर्यातकों के निवेदनों के बारे में कोई आकलन नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणना अपूर्ण है। इसलिए, घरेलू विक्रियों की उपेक्षा करने के बाद में तथा अन्य देशों के निर्यातों अथवा लागतों का उपयोग करते हुए पाटन मार्जिन के लिए तदनुसार थाइलैंड में सामान्य मूल्य का पुनः आकलन करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है।
- xxi. निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए उनको एक अवसर प्रदान करने के लिए एक बैठक के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र इस संबंध में प्राधिकारी को लिखा गया है।
- xxii. मात्रा संबंधी मापदंड निष्पादन में सुधार को दिखाते हैं और आयातों में बढ़ोत्तरी से ठीक पहले वस्तुगत क्षति हो रही है, यह बात कीमत संबंधी मापदंड दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि पाटन हो रहा था अथवा नहीं हो रहा था, इसको ध्यान में न रखते हुए याचिकाकर्ता सदैव क्षतिग्रस्त हो रहा है।
- xxiii. याचिकाकर्ता की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग, याचिकाकर्ता की घरेलू विक्रियां और भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से मात्रा संबंधी सभी मापदंड हैं जो निष्पादन में पर्याप्त सुधार को दर्शाते हैं।
- xxiv. थाइलैंड से आयातों से भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से को प्रभावित नहीं होते हैं।
- xxv. पाटन को ध्यान में न रखते हुए कीमत संबंधी मापदंडों ने सदैव वस्तुगत क्षति दर्शाई है। वर्ष 2014-15 में सबसे अधिक क्षति हुई थी, जब पाटन नहीं था। स्पष्टतः कुछ विजातीय कारक होते हैं जिनसे याचिकाकर्ता को क्षति होती है।
- xxvi. याचिकाकर्ता की प्रचालनात्मक अकुशलताओं की वजह से स्वयं लागत संबंधी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, इसलिए याचिकाकर्ता लागत के अनुरूप अपनी कीमत को समायोजित नहीं कर सका है।
- xxvii. याचिकाकर्ताओं को बढ़ी हुई लागतों को निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत की गई लागतों से सत्यापित किया जा सकता है जो प्रचालनात्मक कुशलताओं की वजह से कम रही है।
- xxviii. थाइलैंड की कीमतें जांचाधीन सभी अन्य देशों की कीमतों से अधिक रहती है। थाइलैंड के लिए आयातों की कीमत कटौती और कम कीमत पर विक्री संबद्ध देशों में सबसे कम रहती है।
- xxix. रोजगार, वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता जैसे कारकों में सकारात्मक वृद्धि देखी जा सकती है।

- xxx. "कोई दीर्घकालिक व्यवहार्यता नहीं है", यह कथन अनुमानित रहता है क्योंकि याचिकाकर्ता को निरंतर क्षति होती है चाहे (कथित) पाटन हो अथवा न हो। याचिकाकर्ता की लागत अकुशलता की वजह से है, इसको ध्यान में रखते हुए इसे और आगे समर्थन दिया जाता है।
- xxxi. प्राधिकारी का खतरा संबंधी विश्लेषण गलत होता है जबकि पाटन बिक्रियों की तुलना में आयात सदैव भारी भरकम होते हैं, यह नोट करना होगा कि याचिकाकर्ता की क्षमता, उत्पादन और बिक्रियां किसी शुल्क के बिना भी जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक रही है।
- xxxi. यह दर्शाने के लिए कोई विश्लेषण किया गया प्रतीत नहीं होता है कि भारत के लिए निर्यातों के लिए अधिशेष क्षमताओं (यदि कोई हो) का उपयोग किया जाएगा। वैश्विक रसायन संयंत्रों की भारी भरकम क्षमता होती है जो मापदंड की मितव्ययिता समेत विभिन्न तथ्यों पर आधारित होती है। थाइलैंड घरेलू और निर्यात मांग को पूरा करता है और कीमत संबंधी प्रमाण स्पष्टतः पाटन के लिए किसी कारण को नहीं दर्शाता है।
- xxxiii. याचिकाकर्ता घरेलू बाजार की मांग को पूरा नहीं कर रहा है। यह भी नोट करना होगा कि चीन और ताइवान याचिकाकर्ता के लिए एक वास्तविक और स्पष्ट खतरा न केवल ऐतिहासिक कारणों की वजह से है, अपितु क्षमताओं के अधिक होने की वजह से है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में कीमतें भी थाइलैंड की कीमतों की तुलना में कम रहती हैं।
- xxxiv. कच्चे माल की आपूर्ति की वजह से याचिकाकर्ता को क्षति हो रही है, उसका उत्पादन/आपूर्ति ज्यादातर जलवायु की परिस्थितियों से प्रभावित होती है और उसने अतः याचिकाकर्ता की लाभप्रदता को प्रभावित किया है (इसका कारण यह है कि कॉटन लाइमर का उपयोग विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किया जाता है)।
- xxxv. याचिकाकर्ता निर्यात बाजारों में भी घरेलू कीमतों के रूप में उन्हीं कीमतों की वसूली कर रहा है जिसके बारे में प्रतिबंध/दबाव अथवा क्षति का कोई प्रमाण नहीं होता है। याचिकाकर्ता की कथित क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध आयातों की अपेक्षा वैश्विक कीमत प्रवृत्तियों से भी अधिकांश होती है।
- xxxi. प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया है कि निर्यात बाजार में हानियां/क्षति, यदि कोई हो, संयंत्र बंदी, पानी की कमी आदि को क्षति विश्लेषण में याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत घरेलू बाजार के निष्पादन के लिए छोड़ दिया जाता है।
- xxxi. निर्यातक यह दोहराते हैं कि वर्तमान जांच में शुल्क लगाने का कोई आधार नहीं होता है और यदि सभी शुल्कों की सिफारिश की जानी चाहिए तो निर्यातक यथा मूल्य रूप में शुल्क की सिफारिश पर कृपया विचार करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं।
- xxxi. क्षति संबंधी अधिकांश मापदंडों को जांच की अवधि (वार्षिक) आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है, तथापि, कुछ शेष मापदंडों के लिए जांच की अवधि के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसलिए, क्षति विश्लेषण को जांच के अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया गया नहीं कहा जा सकता है। ऐसे विश्लेषणों के लिए चैरी पिकिंग आंकड़ों के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- xxxi. उपरोक्त तर्क एडीए के अनुच्छेद 3.1, रक्षोपाय पैनल रिपोर्ट – लौह और इस्पात उत्पादों के आयातों पर कुछ भारतीय उपाय तथा पाटनरोधी नियमावली से लिए गए हैं। इसके अलावा, जांच की अवधि (ए) के लिए

क्षति विश्लेषण किया गया है, लेकिन जांच की अवधि के लिए पाटन मार्जिन की गणना की गई है। कारणात्मक संबंधी अलग-अलग किए हैं क्योंकि ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जो यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान पाटन से क्षति हुई है।

- xl. याचिकाकर्ताओं ने कई आधारों पर गोपनीयता का दावा किया है जो प्रतिवादियों को उनके हितों की समुचित रूप से रक्षा करने के अधिकारों से वंचित करते हैं। नियम 7(i), स्टेलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य को सुनिश्चित करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार के द्वारा की गई किसी आपत्ति को छोड़कर निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा किसी हितबद्ध पक्षकार के द्वारा दावा की गई गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होना होगा।
- xli. याचिकाकर्ताओं की गोपनीयता के दावों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि वे क्षति के महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों का कार्य करते हैं। विगत जांचों में क्षमता के लिए वास्तविक आंकड़ों, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, निर्यात बिक्रियों आदि जैसे मापदंडों को गोपनीय नहीं माना है जिनमें एक अकेला उत्पादक याचिकाकर्ता था।
- xlii. प्रकटन में यह गलत ढंग से नोट किया जाता है कि गोपनीयता के मुद्दे पर विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं की अत्यधिक गोपनीयता के बारे में जोरदार ढंग से विरोध किया है।
- xliii. घरेलू उद्योग और नगर पालिका तथा सिंचाई विभाग के बीच में हुए समझौते के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बताया नहीं गया है। ऐसे मामले में मुद्दों से संबंधित हितों की रक्षा करने के लिए टिप्पणियां नहीं दी जा सकती हैं। उक्त समझौता सार्वजनिक में उपलब्ध नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या समझौते के बारे में गोपनीय अथवा अगोपनीय रूप में दावा किया गया है। गोपनीय दस्तावेज अथवा इसके पीछे तर्क संबंधी सारांश किसी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रमाण लिखित में नहीं लेना चाहिए।
- xliv. घरेलू उद्योग के द्वारा आपूर्ति किया गया विचाराधीन उत्पाद आयातों की तुलना में घटिया गुणवत्ता का है जैसा कि रंग में अंतर होने से देखा जा सकता है। आयातित वस्तुएं घरेलू उद्योग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आसानी से भी भरपूर मिल जाती हैं। खतरनाक और ज्वलनशील प्रकृति के पदार्थ होने के गुणों वाले विचाराधीन उत्पाद में ज्यादा खतरा होता है।
- xlvi. आयातित विचाराधीन उत्पाद बोर्ड के ड्रमों (घटिया थर्मल कंडक्टिविटी) में बंद होता है जबकि घरेलू उद्योग इनको धातु के ड्रमों में बंद करता है जिससे खतरनाक जोखिम बना होता है।
- xlvi. घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरण स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी हुई है। चूंकि, घरेलू उद्योग पूरी अवधि के दौरान लाभ अर्जित कर रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग एक अकेली उत्पाद कंपनी है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ लेना संभव नहीं है।
- xlvi. प्रकटन में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्षों से प्रतिवादी सहमत हैं और यह दर्शाते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (ए) में क्षमता में 82 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और इसी अवधि में क्षमता उपयोग में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यह इस बात को दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।

- xlvi. प्रकटन में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्षों से प्रतिवादी यह दर्शाते हुए सहमत हैं कि घरेलू उद्योग का मालसूची स्तर उद्योग मानदंडों के भीतर हैं। इसके अलावा, उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने के बावजूद घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अथवा निर्यातों में अपने सम्पूर्ण उत्पादन को बेचने में समर्थ है। तथ्य यह दर्शाते हैं कि बिल्कुल भी क्षति नहीं हुई है।
- xlix. रोजगार और मजदूरियों के मापदंडों के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष पर सहमति है और अंतिम निष्कर्षों में इसका पुष्टि होनी चाहिए।
- i. वस्तुगत क्षति के खतरे को सुनिश्चित करने में घरेलू उद्योग असफल हुआ है और प्रकटन कानूनी तौर पर त्रुटिपूर्ण है। यह निर्णय दिया गया है कि आयातों में बढ़ोत्तरी हुई है, तथापि इसके समर्थन में बाद के किसी जांच की अवधि के आंकड़े दिए बिना दावा किया गया है।
 - ii. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बाद के जांच की अवधि के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ब्राजील से पहुँच मूल्य में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगभग 10 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ है। इसका संचयी प्रभाव यह होगा कि बाद के जांच की अवधि के आंकड़ों में कीमत कटौती और क्षति मार्जिन नकारात्मक होगा। अतः वस्तुगत क्षति का कोई खतरा नहीं है।
 - iii. ब्राजील में अधिशेष क्षमता के सूचना स्रोत के बारे में घरेलू उद्योग के द्वारा नहीं बताया गया और इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केवल अधिशेष क्षमता अप्रयुक्त क्षमताओं के बारे में सूचित नहीं करती है अथवा इनका उद्देश्य भारत अथवा निर्यातों के लिए अपवर्तन करना होता है।
 - liii. जांच की अवधि में संशोधन की आवश्यकता होती है क्योंकि अंतर 6 महीने से अधिक होता है। प्रकटन में इसका तर्क नोट कर लिया गया है लेकिन इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है।
 - liv. गैर-टैरिफ रोक जांच की सीमा से बाहर है, इस तथ्य पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष के बारे में सहमति है और अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि होनी चाहिए।
 - lv. मांग और आपूर्ति में अंतर होने के मामले में घरेलू उद्योग के द्वारा पूरी की जा रही मांग के संबंध में ही पाटन हो सकता है और न कि शेष मांग के बारे में जिसकी पूर्ति आयातों से की जा रही है। इसके लिए किसी प्रकार की क्षति का दावा नहीं किया जा सकता है।
 - lvi. चूंकि, प्रतिवादियों को यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बुनियादी सीमा शुल्क को गणना में शामिल किया गया है, इसलिए ब्राजील से आयातों पर पहुँच मूल्य की पुनः गणना करने की जरूरत है। प्रतिवादी (ब्राजील के कुल आयातों के 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत आयातों के लिए) ब्राजील के एक निर्यातक का एक मात्र एजेंट है और प्रकटन में दर्शाए गए मूल्य से आईक्यूआर अधिक (3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत) पहुँच मूल्य को दर्शाता है।
 - lvii. प्रतिवादी यह दोहराते हैं कि घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण निर्यात स्थिति, उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी, गुणवत्ता और पैकिंग संबंधी मुद्दे, तथा अन्य घरेलू उत्पादकों के द्वारा बाजार हिस्से पर कब्जा जमाना जैसे अन्य कारक मौजूद हैं जिनके कारणात्मक संबंधी विच्छेद हुए हैं। इसके अलावा, जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग कोई क्षति विश्लेषण करने में असफल रहा है।
 - lviii. विभिन्न मापदंडों का समग्र निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। अतः वस्तुगत क्षति के खतरे अथवा क्षति का कोई दावा नहीं पाया गया है।

- lix. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। क्षमता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, इसके अलावा, उत्पादन बिक्रियों और क्षमता उपयोग में सुधार दर्शाया गया है।
- lx. इंडोनेशिया से आयातों के कारण लाभ में कमी नहीं हुई है और इनसे कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि इंडोनेशिया से आयात सबसे कम था।
- lxi. घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का वास्तविक कारण याचिका के द्वारा अधिक विस्तार करना है। इंडोनेशिया के निर्यातक ने जांच में सहयोग किया है और इंडोनेशिया के निर्यातक ने जांच में सहयोग दिया है और इंडोनेशिया के निर्यातक के द्वारा प्रस्तुत गणना को स्वीकार कर लेना चाहिए। नियमावली के अनुरूप पाटन मार्जिन की गणना संभवतः किसी पाटन को नहीं दर्शाती है।
- lxii. इंडोनेशिया के आयात याचिकाकर्ता के साथ प्रतिस्पर्द्धा में नहीं है और इंडोनेशिया के निर्यात भारत की मांग और अनुप्रवाह उद्योग के पूरक हैं। किए गए निवेदनों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जांच को समाप्त कर देना चाहिए।
- lxiii. प्राधिकारी के द्वारा पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह जनहित के विरुद्ध है। घरेलू उद्योग के द्वारा बेचा गया उत्पाद अधिक कीमत का होता है और कम गुणवत्ता का होता है। यदि शुल्क लगाया जाता है तो प्रयोक्ताओं के पास याचिका से उत्पाद खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- lxiv. याचिकाकर्ता अविश्वसनीय और प्रतिकूल होता है क्योंकि उनकी आपूर्ति समनुरूप नहीं होती है और डिलीवरी अनुसूचियों का पालन नहीं करती है।
- lxv. भारत में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक विनिर्माता अर्था निट्रेक्स केमिकल है, दूसरा उत्पादक बहुत छोटे स्तर का है और वह अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद नहीं बेचता है। निट्रेक्स केमिकल उत्पाद की अधिक कीमत लेता है और बाजार में उसका एकाधिकार है।
- lxvi. पेंसिल शिक्षा से संबंधित उत्पाद है और सरकार ने इंडोनेशिया एवं थाइलैंड से इसका आयात शुल्क शून्य रखा है ताकि ग्राहकों को नाइट्रोसेलुलोस आसानी से उपलब्ध हो सके।
- lxvii. शुल्क लगाने से लागत बढ़ जाएगी और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में बाधा आएगी।
- lxviii. घरेलू उद्योग काफी ऊंची दर पर संगत ग्रेड के उत्पाद की खुदरा बिक्री करता है और उत्पाद की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होती है। शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग के पास सीमित विकल्प होंगे।
- lxix. शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग को न केवल अपने वाणिज्यिक हित के साथ समझौता करना पड़ेगा, अपितु अनुप्रवाह उत्पाद की गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ेगा।
- lxx. याचिकाकर्ता अत्यधिक अविश्वसनीय है क्योंकि वे सुपुर्द करने की नियत तारीख के भीतर ऑर्डरों की सुपुर्दगी करने में असफल रहते हैं और अंततः सभी शेयरधारकों के हित को खतरा बना रहता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद की गई टिप्पणियों/अनुरोध में अधिकतर पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया गया है और इनकी उपयुक्त और पर्याप्त रूप से जांच की गई है और प्रकटन विवरण या वर्तमान

जांच परिणाम में पहले से ही उचित ढंग से समाधान कर दिया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में निम्नानुसार विचार किया है :-

- i. इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा जहाँ कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, इस जाँच परिणाम पर विचार किया गया है।
- ii. जहाँ तक क्षति और कारणात्मक संबंध तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहाँ किए गए क्षति विश्लेषण स्वतः यह सिद्ध होता है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- iii. पीटी आईयूपी के पाटन मार्जिन की गणना के तर्क के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि निर्यातक ने प्रकार के आधार पर जानकारी प्रदान की है, इसलिए निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किए गए प्रकारों की निर्यात कीमत की तुलना समान संबंधित प्रकारों की घरेलू बिक्री कीमत के साथ की है।
- iv. कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों जैसे सार्वजनिक बयानों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- v. जहाँ तक याचिकाकर्ता की पात्रता के मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता जांच की अवधि के दौरान कथित पाटित वस्तु के किसी आयातक या किसी भी निर्यातक से संबंधित नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को अपात्र घरेलू उद्योग के तौर पर व्यवहार किया जाना उपयुक्त नहीं पाया है।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयात किए जाने वाले उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है और प्रयोक्तओं/आयातकों द्वारा इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, इसलिए बिना किसी ठोस साक्ष्य के हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए ऐसा सिद्ध करने के लिए उठाए गए मुद्दों को नहीं माना जा सकता है।
- vii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहाँ भी आवश्यक हो और ऐसी सूचनाओं को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकटन नहीं किया गया है।
- viii. जनहित संबंधी दलील के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य, आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा, और इसलिए यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
- ix. इस दलील के संबंध में कि नोबेल एनसी और नाइट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड की घरेलू कीमतों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि थाईलैंड में जीएएपी के अनुसार उत्पादकों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर बिक्री कीमत निर्धारित की गई है और उसे यह मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त पाया गया है कि क्या घरेलू बाजार में बिक्री व्यापार की सामान्य

प्रक्रिया में की गई हैं। किसी भी तरह से, निर्यातकों ने स्वयं स्वीकार किया है कि थाई सेना संबंधित उत्पाद के केवल भंडारण और उपयोग को नियंत्रित कर रही है और आपूर्तिकर्ताओं को थाई बाजार में उत्पाद की आपूर्ति करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अधिकांश देशों में एक जैसी है जहां उत्पादों का उपयोग विस्फोटक पदार्थों या किसी अन्य खतरनाक पदार्थ के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। केवल लाइसेंस प्रक्रिया का मतलब यह नहीं है कि घरेलू बिक्री कीमत व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हो सकते हैं।

- x. जहां तक मांग-आपूर्ति के अंतर संबंधी तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, तो ऐसा सामान्य मूल्य के बराबर मूल्य पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात करके किया जा सकता है, न कि बाजार पर कब्जा करने के लिए पाटित कीमत पर। इस तर्क के संबंध में कि चीन और ताइवान वास्तविक खतरा हैं, यह दोहराया गया है कि ताइवान से आयात पीओआई में न्यूनतम सीमा से कम हो गया है। जबकि चीन से आयात पीओआई में न्यूनतम सीमा से बाहर हैं, चीन से आयात की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में कुल आयातों, उत्पादन और खपत की दृष्टि से तेजी से गिरावट आई है। लागू सीमाशुल्क को जोड़ने के बाद चीन से आयात कीमत संबद्ध देशों से काफी अधिक है। इसके अलावा, पूरी क्षति की अवधि के दौरान, चीन से आयातों की पहुंच कीमत संबद्ध देशों की तुलना में अधिक थी और इससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंच सकती थी।
- xi. शुल्क के रूप के संबंध में अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी का अधिदेश कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करना है और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करना है, जिसे यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, पाटनरोधी उपायों के रूप की उपयुक्तता का निर्धारण किसी मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

सिफारिशें

102. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:
 - i. संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात, सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है।
 - ii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
 - iii. यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।
103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी। पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन इनमें से जो भी कम हो के बराबर लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ,

विचाराधीन उत्पादों के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है।

104. कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए विषय देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दिए गए शुल्क तालिका के कॉलम सं. 7 में बताई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल पर विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	रकम	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.		नॉन-प्लास्टिसाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड नाइट्रोसेल्युलोज इसोप्रोपिल अल्कोहल में भीग गया, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 10.7% से 12.2% थी।	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड या नोबेल नेकां कं, लिमिटेड		किग्रा.	यूएस \$
2	3912	-उपरोक्त अनुसार-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	1 के अलावा कोई भी निर्माता।	0.906	किग्रा.	यूएस \$
3.	3912	-उपरोक्त अनुसार-	थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	0.906	किग्रा.	यूएस \$
4.	3912	-उपरोक्त अनुसार-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	पीटी आईएनटीआई सेलुलोसुटामा	0.235	किग्रा.	यूएस \$
5.	3912	-उपरोक्त अनुसार-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	4 के अलावा कोई भी निर्माता।	0.475	किग्रा.	यूएस \$
6.	3912	-उपरोक्त अनुसार-	इंडोनेशिया के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	0.475	किग्रा.	यूएस \$
7.	3912	-उपरोक्त अनुसार-	ब्राज़िल	ब्राज़िल सहित कोई भी देश	कोई भी	0.646	किग्रा.	
8.	3912	-उपरोक्त अनुसार-	ब्राज़िल के अलावा कोई भी देश	ब्राज़िल	कोई भी	0.646	किग्रा.	यूएस \$

105. केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद इस जांच परिणाम के विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जाएंगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

FINAL FINDINGS

Subject: Antidumping duty investigation concerning imports of “Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet” originating in or exported from Brazil, Indonesia, and Thailand.

F. No. 6/12/2018-DGAD—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules) thereof, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), received a written application by M/s Nitrex Chemicals India Limited (hereinafter also referred to as “Petitioner” or “Applicant” or “DI”) on alleged dumping of “Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose, excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet” having nitrogen content in the range of 10.7% to 12.2% (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from Brazil, Indonesia and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries).

And Whereas, the Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant justifying initiation of Antidumping investigation, issued a public notice vide Notification No. 6/12/2018 – DGAD dated 10.04.2018 in accordance with the Rule 5 of the Rules to examine and determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of Antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry (DI).

A. GENERAL PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to this investigation, after the issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
 - i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the Anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority sent a copy of the Initiation Notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/ exporters from the subject countries, known importers/ consumers/ users/ associations in India, other Indian producers and the DI as per the addresses made available and requested them to make their views known in writing within 40 days of the Initiation Notification.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/ exporters and to the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/ producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject countries.
 - v. The Authority sent Exporter’s Questionnaire and Supplementary Questionnaire to the following known producers/ exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Nobel NC Co., Ltd.
 - b. Nitro Chemical Industry Ltd.

- c. Nitro Quimica Brazil
- d. PT. Indocera Utama Precisi;
- vi. A request for an extension of time for filing the exporter questionnaire response was filed by the Brazilian exporter Nitro Quimica Brazil, the Authority granted an extension of 15 days to file exporter questionnaire response. However, no exporter questionnaire response was received on behalf of Nitro Quimica Brazil
- vii. In response to the Initiation Notification, the following exporters/ producers responded and submitted questionnaire responses:
 - a. PT. Indocera Utama Precisi
 - b. PT Inti Cellulose Utama Indonesia
 - c. Nobel NC Co., Ltd.
 - d. Nitro Chemical Industry Ltd.
- viii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Akzo Nobel India Limited;
 - b. Asha Penn Color Pvt. Ltd.;
 - c. Esdee Paints Limited;
 - d. Flint Group India Pvt. Ltd.
 - e. Hi-Tech Inks Pvt. Ltd
 - f. Hindustan Pencils Pvt. Ltd.
 - g. Huber Group India Pvt. Ltd.
 - h. Kansai Nerolac;
 - i. Setco Chemicals India Pvt. Ltd.
 - j. Sheenlac Paints Limited;
 - k. Siegwerk India Pvt. Ltd;
 - l. Sunshine Paints
 - m. Tata Paints;
 - n. Wembley Paints & Chemicals
- ix. The Authority sent User's Questionnaires to the following known importers/ consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with trade notice no 10/2018 dated 7th September 2018:

-
- a. Aakar Paints
 - b. Marigold Paints;
 - c. Ideal Coting Industries;
 - d. Nippon Paints India Ltd.
 - e. Kansai Nerolac Paints Ltd;
 - f. Sheenlac Paints Corp P. Ltd;
 - g. Hero Paints Pvt Ltd;
 - h. Archana Color Coatings;
 - i. Meet Paints Pvt. Ltd.;
 - j. Kokuyo Chemlin Limited;
 - k. Across Coatings (P) Ltd;
 - l. Krishna Murari Organosys;
 - m. Jubliant Agri and Consumer Products Ltd.
- x. The following importers and users of the subject goods responded by filing questionnaire responses:
- a. Chem Pharma Impex
 - b. Esdee Paints Ltd.
 - c. Tara Paints and Chemicals
 - d. Arihant Resins & Pigments LLP.
- xi. The initiation notification was also sent to the associations listed below:
- a. India Paints & Coatings Association;
 - b. India Small Scale Paints Association;
 - c. Indian Paints & Power Coatings Manufacturers Association;
 - d. All India Printing Ink Manufacturers Association
- xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xiii. The request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of import of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

- xiv. The Non-Injurious Price (NIP), based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the DI on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Antidumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether Antidumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the DI.
- xv. The Authority held an oral hearing on 6th August, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6), which was attended by the representatives of DI, representatives of exporter of Thailand, representatives of Indonesian exporter, Embassy of Indonesia, importers, and users. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were requested to submit their rejoinder thereafter. The users present in the hearing were asked to file the user's questionnaire response along with their written submissions. Following which the following users filed user's questionnaire response
- a. Esdee Paints
- b. Arihant Pigments and Resins LLP
- xvi. The verification of the information provided by the DI was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- xvii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 2016-September 2017 (18 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2013 - March 2014, April 2014 - March 2015, April 2015 - March 2016 and the POI. In order to present an appropriate comparison of the POI figures with other years, wherever the data has been mentioned for the entire injury period, the data for the POI has been presented on an annualized basis.
- xviii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.
- xix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on a confidential basis. The exporters were asked to file a revised non-confidential version of the exporter questionnaire response and provide all necessary and relevant information. A revised non-confidential version of the questionnaire was filed by the responding exporters.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 7th December 2018 to the concerned interested parties. Comments were requested by 14th December 2018. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
- xxii. '***' in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as ₹ 67.06 = 1 US\$.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**B.1 Views of the Domestic Industry**

2. The views of the DI are as follows:

- i. The product under consideration is non-plasticized Industrial grade Nitrocellulose excluding nitrocellulose damped in ethanol and water-wet (hereinafter will be called as the "PUC"), having nitrogen content in the range of 10.7% to 12.2%.
- ii. The industrial nitrocellulose is of two types, one is solvent (solvent damped) i.e. non plasticized nitrocellulose and other is plasticizers damped. Non-plasticized nitrocellulose is basically solvent damped based nitrocellulose which is used for industrial purpose.
- iii. There are three kinds of damping media viz. Normal Butyl Alcohol (NBA) damped, Isopropyl Alcohol (IPA) damped and Ethyl Alcohol damped and the fourth type of non-plasticized nitrocellulose is water-wet, which can be damped in any medium.
- iv. Non-plasticized nitrocellulose (NC) damped in IPA and damped in NBA serves the same purpose and is interchangeable for the paint industry.
- v. The product under consideration is known to be one of the oldest film formers unequaled in properties like toughness, durability, fast solvent release capacity and solubility.
- vi. The major raw material of the product under consideration is pulp, i.e. cellulose which is obtained from purified cellulose either in the form of cotton linter or wood pulp.
- vii. The product under consideration is 'Industrial grade Nitrocellulose damped in Isopropyl Alcohol' is measured in terms of KG and classified under customs sub-heading 39122019.
- viii. There is no known difference in the product produced by the petitioner and exported from the subject countries. The consumers are using the two interchangeably. Subject goods produced by the petitioner are like the article to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Antidumping Rules.
- ix. The product under consideration can be produced with cotton linter or wood pulp as raw materials. The raw material is chosen by petitioner based on their prices or climate conditions. There was no shortage of raw material and DI has never suffered an injury on this account.
- x. There is no quality issue with the product under consideration being sold by the petitioner because users like Esdee paints have been purchasing the PUC from the petitioner since last 25 years and has never made complaints with regard to quality of the product.
- xi. The users have shifted to imports, not because of better quality but cheap prices being offered by them. So the allegation with regard to quality is completely baseless and the opposing interested parties have not submitted any evidence in this regard and have merely made an allegation
- xii. Petitioner caters to large MNC's and Indian companies, to almost all small-scale companies and to over 25 countries in the world. All these clearly show Nitrex quality is of International standards.
- xiii. Quality of packing of the PUC has never been an issue and the packaging given by the petitioner is absolutely safe.

B.2 Views of Interested Parties

3. Other interested parties have made the following submission:

- i. The quality of the subject goods produced by the Petitioner is of low quality in comparison to the subject imports.
- ii. The PUC is highly inflammable and hazardous and the DI packs the material in poor packing boards whereas the imported product is properly packed in fiberboard material.
- iii. The quality of the product is determined by its colour and the product is of white coloured cotton form but the product supplied by the DI is pale in colour which indicated inferior quality.
- iv. The product imported is more free-flowing, thus easy to handle whereas the product supplied by the DI is less free-flowing and is difficult to handle.

B.3 Examination by the Authority

4. The product under consideration in the present investigation is “Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet having nitrogen content in the range of 10.7% to 12.2%” (also described as Nitrocellulose and also referred to as subject goods).
5. The product under consideration has properties like toughness, durability, fast solvent release capacity and solubility. The product under consideration is a flammable compound formed by nitrating cellulose through exposure to nitric acid or another powerful nitrating agent and it is used in the manufacture of Wood Lacquers, Auto Refinish Paints, Leather Finishing Lacquers, Nail Varnishes, and Printing Inks etc. The product does not form a major proportion in the cost of production of any of the downstream product.
6. The major raw material of the product under consideration is pulp, i.e. cellulose which is obtained from purified cellulose either in the form of cotton linter or wood pulp. While the weight of the product is 70% nitrocellulose, this is sold damped in a suitable solvent (30%) so as to prevent the nitrocellulose from igniting. The Authority has noted that while the Nitrocellulose is normally damped for use in Isopropyl Alcohol (IPA) for the paints and varnishes industry, it is largely only in India that Nitrocellulose damped in Normal Butyl Alcohol (NBA) is also used. However, no trade/ import into India have taken place from the subject countries of Nitrocellulose damped in NBA during the POI.
7. However, considering that there is a significant price difference between NBA and IPA, no import of ‘Nitrocellulose damped in NBA or Butanol’, no known production of ‘Nitrocellulose damped in NBA in the subject countries and limited interchangeability of Nitrocellulose damped in NBA and damped in IPA, the Authority has restricted the scope of PUC only to “Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose Damped in Isopropyl Alcohol having Nitrogen content in the range of 10.7% to 12.2%”.
8. The subject goods are classified under the Chapter 39 under Customs subheading no. 3912 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation. The import data shows that the product has been reported under Customs classification of 39122019.
9. The interested parties have raised a concern about the quality of the domestic product. The Authority, however, notes that there is no quantified evidence provided by these interested parties to show the alleged quality difference between the domestic and imported product. It is also noted that the DI has provided evidence showing that some of the consumers increased their sourcing more from imports and reduced from DI. These consumers, however, continued to buy significant volumes from the DI, thus clearly showing that these parties were nevertheless buying significant volumes of the product from the DI. On the spot verification conducted at the premises of the petitioner DI and the exporter from Thailand did not show any material difference in the product supplied by the DI and foreign producers. The increased sourcing by the consumers from imports at lower prices while continuing to buy from the DI at relatively higher prices also shows that the consumers have shifted to imports because of the lower prices offered by foreign producers and not due to the alleged difference in the quality of the product.
10. As regards the quality of the packaging of the product, the Authority notes that it has not been established how the difference in packaging renders the two products as different products. It is also noted the petitioner has been selling the product for past quite some time and there is no verifiable evidence to show that difference in

the quality of packing is leading to higher imports. The petitioner contended that it supplies the product in Mild Steel Drums which is considered much stronger and durable when compared to fiberboard drum packing or corrugated box packing of imports. It is also noted that the DI has been exporting the product and its exports doubled over the present injury period.

11. With regard to like article, Rule 2(d) of the Antidumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

12. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the product under consideration exported from subject countries and the subject product produced by the DI. The subject goods produced by the DI is comparable to the subject goods exported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
13. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the DI are like article to the product under consideration exported from the subject countries, in accordance with the Antidumping Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Views of the Domestic Industry

14. Following submissions have been made by the DI:

- i. The Authority may undertake elaborate investigations and find out the standing of the petitioner. Petitioner has no reservation. The facts would clearly establish that the production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production.
- ii. Cumulating production of all other producers would be misleading for the reason that one of the producers has started its production at a different point in time and M/s. UNIX Cellulose Pvt. Ltd. has commenced production within the injury period itself.

C.2 Views of Interested Parties

15. The following submissions have been made in this regard:

- i. There are other producers of the PUC in India, namely GRN Cellulose Pvt. Ltd. and Unix Cellulose Pvt. Ltd. Thus, it should be verified if Petitioner does constitute a "major share" of production in India.

C.3 Examination by the Authority

16. The application has been filed by M/s Nitrex Chemicals India Limited as a domestic producer of the subject goods who has provided detailed information for the present investigation. The petitioner identified GRN Cellulose Pvt Ltd and UNIX Cellulose Pvt. Ltd. as other Indian producers of the product. There is no other known producer of the subject goods in India.
17. The Authority considered the contention of the interested parties regarding the examination of the petitioner as constituting major share in the production in India. The Authority has considered the production of the petitioner and other Indian producers. It is noted that two of the reported 'other producers' have not responded to the Designated Authority in the present investigations. Information on record shows that while one was producing during the entirety of the injury period, the other started producing only in 2015-16. This information was provided by the petitioner, barring who none of the other interested parties have provided any specific data/information about these producers. The Authority has, therefore, based on the information before it quantified

the total Indian production and has determined that the production of the petitioner in the POI constituted 71%, whereas, the production of the other two domestic producers constituted the balance 29%.

18. The petitioner has neither imported the subject goods nor is related to any of the importer or exporter of the subject goods. Thus, after consideration of various relevant aspects, the Authority has determined that the petitioner is eligible to be treated as DI under the law and its production constitutes a major proportion in Indian production.
19. It is, thus, determined that the petition has been made by and on behalf of the DI, the petitioner satisfies the requirement of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules and the petitioner constitutes 'DI' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. ISSUES RELATED TO CONFIDENTIALITY

D.1 Views of the Domestic Industry

20. The DI made the following submissions:
- i. The responding exporters have resorted to excessive confidentiality claims which have completely prevented the Petitioner from offering their comments. The confidentiality claims are not in accordance with Rule 7 of the rules.
 - ii. None of the parties have given even an indexed version of their performance indicators. Injury statements filed by the DI are invariably either on actual basis or on an indexed basis.
 - iii. In the instant case, the information could have been easily indexed. Despite so, the information has been completely suppressed.
 - iv. Injury statement filed by the petitioner can be seen. DI being a single company has provided indexed figures of each parameters showing the trend of injury parameters, the exporters opted to not provide even the non-confidential summary of the performance parameters as sought in Appendix 1.
 - v. The interested parties have not disclosed all such information that they are obliged to disclose under the Rules. Even information that is publicly available has not been disclosed in the non-confidential version.
 - vi. The users also have resorted to excessive confidentiality and have not filed the NCV user's questionnaire containing sufficient information to permit substance of the information provided on a confidential basis. The DI is not able to defend its interest and respond to a questionnaire response filed by them.
 - vii. The Trade Notice no 05/2018, dated 28th February 2018 suggests that the interested parties are required to file a nonconfidential summary of every confidential information filed.

D.2 Views of Interested Parties

21. There have been no submissions made by the opposing interested parties.

D.3 Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Antidumping Rules provides as follows:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the Designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its

confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The Designated Authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential. The Authority directed the exporters to file a revised non-confidential version of questionnaire response and provide a meaningful response. The responding exporters filed a revised response. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of a public file.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Views of the Domestic Industry

24. The following miscellaneous submissions have been made by the DI:
- i. The allegation of the opposing interested parties provides only half the truth of the situation and the news articles specifying closure of plant does not fall under a period of investigation.
 - ii. The allegation of plant shutdown of the petitioner is baseless. The petitioner has submitted all the details with regard to a plant shutdown.
 - iii. Petitioner took action on suggested remedies of the Gujarat Pollution Control Board (GPCB), thus, making them withdraw the same order in 15 days. Further, Nitrex plant was never shut down on regulatory issues.
 - iv. The allegation of the opposing party regarding the shortage of water in petitioner's plant is of no relevance. The ongoing agreement of the petitioner with the Government of Gujarat, Municipality and Irrigation department clearly show that the petitioner has no water shortage and they get water supply adequately. Evidence of the same have been filed on record.
 - v. Report of the Expert Committee appointed by High Court of Gujarat (March 2013) and its relevant clauses, which guarantees an adequate supply of water.
 - vi. Average daily consumption of water shows that the average daily availability of water (each month during the last 5 years), was more than required by the petitioner.
 - vii. The POI is April 2016-September 2017 and the initiation of investigations was notified on 10th April 2018. There is no issuer with regard to the POI and initiation of the investigation. The data provided for initiation was recent and examined by the Authority.
 - viii. There are various tariff and non-tariff barriers in the subject countries due to which India is denied free market access. However, India is an open market for these exporters with significant duty concessions and no license requirements.

- ix. Thailand and Indonesia both have exported approximately 300 tons of Nitrocellulose in POI whereas the Indian producers are denied free market access by these countries due to the non-tariff barrier. ‘
- x. Nitrocellulose (both for civil and defense use) is listed as “explosive articles” under the notification of the “Thai Ministry of defense on arms”. As a consequence, the import of industrial nitrocellulose requires a prior import license by the Ministry of Defense under “Arms Control Act”.
- xi. As per the free trade agreement, current imports into India from Indonesia is having 0% customs duty under MFN category. However, imports into Indonesia from India are having 4% customs duty.
- xii. In Brazil, Indian producers will have to obtain an import license where the Ministry of Defense, Brazil is involved, and Import License is denied with an argument of public security and chemical can be used to produce explosives.
- xiii. The customs duty in India for Brazil is 7.25% for the subject goods whereas Indian imports need to pay a customs duty of 14% in Brazil. So the Indian imports in Brazil are subject to both tariff and non-tariff barrier.
- xiv. The questionnaire response filed by ABC Chemicals Pvt. Ltd was much delayed after the prescribed deadline. The questionnaire was filed by the importer after the delay of 49 days despite an extension for filing responses was granted by the Authority.
- xv. The Authority has been very careful about the time limits prescribed and once the Authority rejected a petitioner for delay of merely less than 24 hours. In light of the practice adopted by the Authority, the response filed by ABC Chemical should be rejected.
- xvi. Importer questionnaire filed by Chem Pharma should be rejected on the ground of filing it at a much-delayed stage. The opportunity to file questionnaire response only to the users.

E.2 Views of Interested Parties

25. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties in this regard –
- i. Plants of the petitioner have been shut down by State Authorities twice, due to regulatory issues. Thus, the downturn in performance and the subsequent injury cannot be attributed to the subject imports.
 - ii. Two of petitioner’s plants are in Gujarat and there is a water shortage in the State of Gujarat. Petitioner has been facing water shortage issue from several years, thereby affecting the Petitioner’s production which should also be dominant factor affected the Petitioner’s industry performance.
 - iii. Petitioner stops the supply of the product without any intimation.
 - iv. The POI is not recent and there is a gap of 6 months between the date of initiation and POI. POI should be revised, and the Designated Authority is requested to examine post-POI data till June 2018.
 - v. Indonesian industry believes that this is irrelevant with the current investigation. Moreover, the tariff under all FTAs has been decided based on economic consideration of Government involved with full consideration of the interest of their respective industry.
 - vi. The fact of tariff difference due to ASEAN is irrelevant for the present investigation. The agreements are done by the government looking at the economic consideration with the Government involved with full consideration of the interest of their respective industry.
 - vii. Any levy of duty would make it difficult for the user industry to procure subject goods on account of higher prices in the Indian market.

E.3 Examination by the Authority

26. Various Misc. issues raised by the interested parties have been examined by the Authority. As regards the contention that the petitioner is performing poorly due to shutting down of their plant by the State Authorities twice, the DI has submitted evidence in that regard. The Authority considered the evidence provided by the petitioner and it is noted that the Gujarat Pollution Control Board had issued a plant closure notice to the petitioner; however, the petitioner soon after issuance of notice complied with the directions issued by the Board. The notice of plant closure was revoked and the plant was never shut on that account.
27. The Authority has examined the issue with regard to water shortage in petitioner's plant. It is noted that the petitioner has submitted their agreement with the Municipality and Irrigation department, the Government of Gujarat, which clearly states that the petitioner has an adequate supply of water and there is no plant shut down or production shut down due to a shortage of water.
28. It is also noted that the opposing interested parties have not provided any evidence which goes on to establish that the petitioner had stopped or curtailed the supply of the product suddenly without prior intimation.
29. As regards the argument of non-tariff barriers in the subject countries, the Authority notes the concerns of the DI with regard to these non-tariff barriers in Thailand and Brazil. The Authority, however, considers that the issue is beyond the scope of the present investigation. The interested parties are free to raise such concerns with the appropriate authorities. The purpose of the present investigation is whether the product under consideration is being exported to India at dumped prices and whether the same has caused injury to the DI.
30. As regards the argument of impact on the user industry, the Authority considers this an important aspect of the antidumping action. The intention of the Authority is not to adversely impact the domestic user industry but to ensure that any unfair practices used by the exporters in the subject countries are addressed and, at best, to the extent that these practices are injuring the DI. The interests of the domestic user industry will be considered in this larger context of ensuring that fair and even conditions exist in the domestic market.
31. Regarding the delayed responses filed by some of the interested parties, while the Authority underlines the importance of timelines for the purpose of the investigation, issues of relevance raised in these responses have been taken into consideration to the extent possible.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**F.1 Views of the Domestic Industry**

32. The DI *inter alia* submitted as follows:
- i. CIF import price from Thailand, which seems to be higher than from other subject countries, is not the real import price, as many producers and exporters from Thailand receive special discounts on CIF import price. This was substantiated with communications on price negotiations, with some customers.

F.2 Views of Interested Parties

33. The following submissions have been made with regard to normal value, export price, and dumping margin—
- i. The prices from Thailand to India have been relatively higher than the prices from other countries.
 - ii. Co-operating exporters have filed the requisite information as per the prescribed questionnaire formats and the same should be taken into consideration for according the exporters an individual margin.
 - iii. Various cost factors such as any applicable tax, handling charge and inland transportation including any possible interest incurred at the distribution level have not been considered for the landed price.

- iv. The fierce competition in the Indonesian market suggests that the Indonesian industry is unlikely to set their price higher but to always be at a very competitive level. This is to clearly signal that Indonesia Industry's export price level to India is fair according to fair trade norms of the WTO.
- v. There is no justification that the cost structure of the PUC in India would be representative of Indonesia including the raw material used in the production, power, and labour. Such a flawed assumption cannot reflect the factual cost and sales of Indonesian producer. As such, this dumping allegation does not serve the purpose as evidence in dumping investigation and DGAD should reject this assumption.
- vi. The decline in selling price is due to the decline in cost. There is no price effect on the DI.

F.3 Examination by the Authority

34. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
- (i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
 - (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
35. The Authority sent questionnaires to the known exporters/ producers from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed Exporters Questionnaire Responses:
- a. PT. Indocera Utama Precisi
 - b. PT Inti Cellulose Utama Indonesia
 - c. Nobel NC Co., Ltd.
 - d. Nitro Chemical Industry Ltd.
36. Since the above-mentioned producers/ exporters have filed the questionnaire response, the Authority determines Normal Value and Export Price in respect of cooperative exporters. The general methodology adopted by the Authority for determination of Normal Value for these exporters is to first examine whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal Values on the basis of domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents.
37. In the case of non-cooperating exporters in the subject countries, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules.
38. The Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of producers/ exporters of the subject goods as follows:

F.4 Assessment of Dumping for Exporters from Indonesia**(a) Normal Value of PT Inti Celluloseutama, Indonesia (producer) and PT Indocera Utama Precisi (Exporter)**

39. PT Inti Celluloseutama Indonesia is the producer of the subject goods and is exporting the product under consideration to India through its related company PT Indocera Utama Precisi.. PT. Indocera Utama Precisi is a private limited company incorporated under the law of the Republic of Indonesia is only an exporter of the product under consideration and not a producer of the PUC. The questionnaire response filed by PT Inti Celluloseutama, and its related exporter PT. Indocera Utama Precisi, Indonesia has been examined by the Authority and it is seen that PT Inti Celluloseutama, Indonesia, does not sell the subject goods in the domestic market directly. It sells the subject goods in the domestic market 100% through a related party, Pt Indocera Utama Precisi. The product under consideration is sold by the related party Pt Indocera Utama Precisi, in the domestic market of Indonesia. The adjustment of expenses such as Inland Transportation and Credit Cost has been made towards the determination of domestic sales price in the foreign producer's country. During the POI PT Inti Celluloseutama, Indonesia sold 3351.69 MT of the subject goods in the domestic market through PT Indocera Utama Precisi. All these sales were subjected to an ordinary course of trade test. It was found 94% of the sales in the domestic market were profitable. Accordingly, the normal value for the above producers/exporters work out based on total sales is *** US\$ per MT.

(b) Export price of PT Inti Celluloseutama, Indonesia exported through PT Indocera Utama Precisi, Indonesia (related exporter)

40. It is noted that the Company had made all the exports to India through PT Indocera Utama Precisi, Indonesia (related exporter) directly. It is noted that the aforesaid exporter has also filed a response. The Authority, upon examination of responses filed by both producer and exporter, notes that PT Inti Celluloseutama, Indonesia exported 849.05 MT in total through PT Indocera Utama Precisi, Indonesia. The exporter has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, and commission. The exporter has stated that the adjustments for these expenses have been claimed on the basis of actuals. The Authority has accepted the export price along with all adjustments claimed by them in their response. The export price so determined has been used to determine dumping margin.

(c) All other Producers/Exporters from Indonesia

41. In respect of all other exporters from Indonesia who have been treated non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.5 Assessment of Dumping for Exporters from Thailand**(a) The normal value of Nitro Chemical Industry Ltd. and Nobel NC Co., Ltd.**

42. The questionnaire response has been filed by Nitro Chemical Industry Limited and Nobel NC Co., Ltd, Thailand. Nitro Chemical Industry Ltd. is a producer of the subject goods and is the holding company. Nobel NC Co., Ltd. is also the producer of the subject good and is 100% owned by Nitro Chemical Industries. Both producers/exporters have provided domestic sales price details of the subject goods in Appendix- 4 of their response. Nitro Chemical Industry Limited sells the subject goods to customers directly in the domestic market in Thailand. The adjustment of expenses such as inland freight, bank charges, credit cost, and other expenses has been made towards the determination of domestic sales price in the foreign producer's country. Nobel NC Co.,Ltd, sells the subject goods in the domestic market 100% through the holding company Nitro Chemical Industry. The adjustment of expenses such as inland freight, bank charges, credit cost, storage cost, and other expenses has been made towards the determination of domestic sales price in the foreign producer's country. During the POI Nitro Chemical Industry Limited sold 4193 MT of the subject goods in the domestic market. All these sales were subjected to an ordinary course of trade test. It was found 99.96% of the sales in the domestic market were profitable. Accordingly, the normal value for the above producers/exporters work out on the basis of total sale is *** US\$ per MT.

(b) Export price of Nitro Chemical Industry Limited exported through Nobel NC Co., Ltd

43. It is noted that the Nitro Chemical Industry Limited has made all the exports to India directly as well as through Nobel NC Co., Ltd (related exporter). The related exporter and producer Nobel NC Co., Ltd has exported all the

subject goods to India directly. The Authority has, therefore, taken into account both direct as well as exports through related exporter for the purpose of determining the export price for the responding exporter. The exporter and producers have claimed adjustment on account of shipping cost, ocean insurance, handling charges, inland freight, storage cost, commission, credit cost, bank charges, and other expenses. The exporter and producer have stated that the adjustments for these expenses have been claimed on the basis of actuals. The Authority has accepted the export price along with all adjustments claimed by them in their response. The export price so determined has been used to determine dumping margin.

(c) All Other Producers/ Exporters from Thailand

44. In respect of all other exporters from Thailand who are treated to be non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.6 Assessment of Dumping for Exporters from Brazil

45. Since none of the producer or exporter has filed any exporter questionnaire response, all the exporters/producers of Brazil are treated as non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The petitioner, in the petition, had claimed the normal value of Brazil on the basis of the export price of Nitrocellulose from Brazil to the Third country. Since the prices provided by the petitioner are of Nitrocellulose and further segregation of the product is not available and since Nitrocellulose are produced and sold in different forms, while the evidence was sufficient for the purpose of initiation, the same cannot be considered sufficient for the purpose of determination of normal value. The Authority therefore proposes to determine normal value on the basis of best estimates of the cost of production with reasonable addition for SGA and profits in view of the absence of any public information concerning domestic selling price of the product in Brazil.
46. The Authority notes that none of the exporters have furnished information to the Authority in the form and manner prescribed which could be used for determination of the export price and individual dumping margin. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters in Brazil on the basis of the DGCI&S transaction wise data. The export price has been adjusted on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from subject countries is as shown in the dumping margin table below
47. On the basis of normal value and export price determined as explained above, the dumping margin has been determined for the responding and non-responding producers/ exporters in subject countries, details of which are given in the table below.

Dumping Margin Table

SN	Producer/Exporter	Country	NV/CNV	NEP	Dumping Margin		
			US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
1	Nitro Chemicals Industry Limited / Nobel NC Co., Limited	Thailand	***	***	***	***	40-50
2	Any other than at sl. No. 1	Thailand	***	***	***	***	65-75
3	PT INTI Celluloseutama	Indonesia	***	***	***	***	05-15
4	Any other than at sl. No. 3	Indonesia	***	***	***	***	20-30
5	All producers	Brazil	***	***	***	***	50-60

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Views of the Domestic Industry

48. As regards injury and causal link, the DI has made submissions as under:

- i. Demand for the product under consideration has increased throughout the injury period. It has increased by 44% in the Period of investigation since the base year.
- ii. Imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms throughout the injury period. The share of imports from subject countries constituted about 97% of total imports in India. Imports have also increased in relation to production and demand in India over the injury period.
- iii. There is no demand-supply gap. Even if imports are happening to fill the demand-supply gap, the exporters can do so by selling the product on fair price. The demand-supply gap does not justify dumping.
- iv. The petitioner has lost sales to several prime customers in the last four years. A number of major customers who were buying the subject goods from the DI preferred to shift to imports – either partly or wholly – due to dumped prices offered by the imports.
- v. This loss of sales by the DI is despite adverse prices offered by the DI to face the unhealthy competition of the market. Had the petitioner not lost these consumers, it would have been able to sell more. The petitioner has suffered significant volume injury due to loss of clients.
- vi. There has been a significant price undercutting by the dumped imports from each of the subject countries.
- vii. With the increase in the cost of production in the POI, the selling price of the DI declined. The DI was forced to reduce the selling price to match the import prices of the subject countries in order to sustain in the market. Dumped imports are depressing and suppressing the prices of the DI.
- viii. There is a significant price underselling from each of the subject countries.
- ix. Production and capacity utilization has declined in the POI. The petitioner is faced with unfair trade practices. The petitioner is not suffering any injury due to exports and exports have increased in POI.
- x. The demand of the product under consideration has increased by 44% as compared to a base year and 15% as compared to previous year respectively whereas the domestic sales have increased only by 29% and 5% respectively. It is also important to see that the imports have increased by 38%. The DI has not been able to sell the product in proportion to the increase in demand.
- xi. Even when overall sales of the DI have improved, it would be seen that sales of the DI to few customers very steeply declined. These declines in sales are not due to a decline in consumption by these consumers. This decline in sales is due to the procurement of imported material by these consumers.
- xii. The dumped imports have created a significant pressure in the market and the DI has lost market share in the POI as compared to a preceding year and base year, despite there is an increase in demand.
- xiii. The profitability of the DI has significantly declined throughout the injury period. PBIT and return on capital employed have shown the same trend as that of profitability.
- xiv. The cash profits of the DI have also declined significantly during the period of investigation as compared to base year as well as the previous year. The DI is facing significant price depression in the market. The result of price depression is the severe decline in profit parameters
- xv. Inventories have increased over the injury period. The industry is unable to dispose of its accumulated inventories due to the presence of dumped imports.
- xvi. Petitioner has been able to maintain their sale because they compromise on their price. The other producer has no role to play
- xvii. The growth of the DI in terms of capacity utilization, selling price, profitability, cash profit, PBIT, ROI has been negative.
- xviii. Production, not increase in prices and does not make the profits to be fluctuating.
- xix. Impact of dumped imports from subject countries has caused DI performance to deteriorate and the same is seen from declining trends in ROI, profits, per unit, Cash Profits, capacity utilization, and market share.
- xx. The Net Fixed Assets and wages have been both declined in the POI when compared to the previous year. Working capital has been declining till 2015-16 and then had a minor increase but is still less when compared to the base year.
- xxi. The product under consideration can be made from both cotton linter as well as wood pulp. The petitioner used both depending on the climatic situation. There has been no shortage of raw material at any point of time and petitioner has never suffered an injury on this account.

- xxii. There is a threat of material injury. The exporters have surplus capacities and the imports will intensify further if the duty is not imposed.
- xxiii. Exports prices of the DI vary from country to country depending on the market dynamics of each country. Petitioner's exports prices are much higher than the subject countries prices for exports to India.
- xxiv. The DI has no reservation with regard to checking the post POI data. The data post POI will show an increase in imports and further deterioration in the performance of the DI.

G.2 Views of Interested Parties

49. Submissions made by the other interested parties are as under:

- i. Imports have not increased in both absolute and relative terms. There is no volume injury and the injury suffered, has absolutely no correlation to imports from the Subject Countries. The performance of Petitioner has improved with the increase in Imports.
- ii. Imports are happening on account of the demand-supply gap.
- iii. The imports in relation to demand/consumption, specifically from Thailand, have declined in the POI by 4% in comparison to the base year. The decrease in market share of the Petitioner in POI and in the year 2015-16 is on account of other new Indian producers who have started production of the PUC.
- iv. The landed price of the subject imports has not impacted the net sales realization of the Petitioner thus not causing a price suppression/depression. Despite the decline in the landed price from 2015-16 to the POI, the net sales realization of the Petitioner has increased during the same period.
- v. The petitioner admitted in the oral hearing that their capacity utilization is 90% and they are able to produce goods consistently. There is positive growth in the performance of the DI. The figures provided in format H is different and the Authority should check the accuracy of data provided by the petitioner.
- vi. Based on the market information the capacity of the DI is 11000 MT p.a whereas demand for the subject goods is 13,000 MT pa. DI exports 20-30% of its production so only 8,000 MT p.a is left for domestic sale. There is a lack of reliability and that is the reason customers have opted for imports;
- vii. The Petitioner has been able to exhaust its inventories and have been able to make higher sales in the POI.
- viii. DI has been able to increase its capacity, production, and sales, and controls 70% of the market share. The claim of injury is unfounded;
- ix. Net sales realization is in consonance with the cost of sales in the POI, showing that there is no effect of import prices on the DI performance
- x. The net sales realization and profits have been fluctuating irrespective of the price undercutting being stable in the entire injury period. It can be seen that the Petitioner has been making profits and has been able to maintain the net sales realization.
- xi. Sales of the DI have been increasing steadily growing throughout the injury period. DI's sales performance has been profitable irrespective of the subject imports. Effect on sales, if any, of the Petitioner, is on account of the other new producers entering into the domestic market of the PUC in 2015-16 and not subject imports;
- xii. The Petitioner has been able to exhaust its inventories and have been able to make higher sales in the POI;
- xiii. The number of employees of the DI has increased in the POI and throughout the injury period.
- xiv. The Petitioners having relied on return on capital employed and wages in its injury analysis, but have failed to provide any data on the same.
- xv. Nitrex Chemicals India Limited (Petitioner) failed to present sufficient evidence to comply with Article 5.2 of the WTO Antidumping Agreement (ADA) and as such request the DGTR to reject the petition filed by the petitioner or terminate the current investigation without any protective measure.
- xvi. The injury to the industry is self-inflicted and is due to the expansion made by the petitioner.
- xvii. This remarkable expansion is then consistently sequenced by its top ability to increase its production quantity of the product under investigation (PUC) by 23% during the POI as compared to 2013-2014 and by 4% increment in the POI as compared to 2015-2016.

- xviii. The productivity of the Petitioner experienced a positive increase by 28% during the POI as compared to 2013-2014 and for which increase continued by 5% in the POI as compared to 2015-2016. Petitioner has been able to increase its number of employees.
- xix. The injury to the petitioner is due to expansion made by them. The audited financial report of the petitioner shows that the share of revenue from domestic sales is nearly constant over the last 3 years (2014-2015; 2015-2016 and 2016-2017 and moreover its turnover increased during the same periods.
- xx. Sales of the DI has been increasing steadily growing throughout the injury period. DI's sales performance has been profitable irrespective of the subject imports. Effect on sales, if any, of the Petitioner, is on account of the other new producers entering into the domestic market of the PUC in 2015-16 and not subject imports.
- xxi. One of the plants in which the Petitioner operates was shut down for five years until 2013 due to regulatory issues. Even though the same was recommissioned in 2014, the plant reported experiencing operational losses until the financial year 2017. This is irrefutably due to the severe losses it indeed suffered due to the closure of its plant which cannot be attributable to the import of PUC.
- xxii. The DGTR should examine the fact on the substantial increase in the amount of miscellaneous expenses presented in the Petitioner's profit & loss account in 2016-17 towards for which details are not available. This is a very high amount as compared to 2015-16 and 2014-15 which the DGTR should carefully examine for the interest of causation and non-attribution factor in this investigation.
- xxiii. Petitioner's injury is caused by the global price trends rather than the subject imports, as it can be seen that petitioner has exported the subject goods at similar prices, to markets, where there are no alleged dumped imports to suppress and undercut prices.
- xxiv. Production/supply of cotton liners, which is one of the raw materials, is majorly affected by climatic conditions and the same has consequently, impacted the profitability of the Petitioner
- xxv. The comparable type by type price effect analysis is mandatorily required to reach a correct and fair outcome of the investigation. There is a recent jurisprudence in the WTO in the Panel Report of the EU-imposition of antidumping measure against Indonesia (DS 480) that the price effect analysis is to be made on a comparable basis whereby type by type price analysis is required.
- xxvi. The export from Indonesia to India is to complement the DI and help the downstream industry.

G.3 Examination by the Authority

- 50. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the DI in accordance with the Antidumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties.
- 51. Regarding the argument of the accuracy of data provided by the petitioners, it is noted that the findings of the Authority are based on the verified data.
- 52. With regard to the argument of demand-supply gap, the Authority notes if there is a demand-supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the country by bringing the product at a fair price. Demand-supply gap does not justify dumping of the product.
- 53. The Authority notes the argument of the petitioner that the Domestic industry lost significant share in the demand for the product by a number of customers due to cheap imports.
- 54. The submissions made by the DI and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:
- 55. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on DI. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared

with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. As regards the consequent impact of dumped imports on the DI, Para (iv) of Annexure II of Antidumping Rules states as under:

(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the DI concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments

56. The Authority considers all injury parameters and thereafter concludes on the basis of collective and cumulative examination of all the parameters whether the DI has suffered injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts, figures, and arguments submitted by the interested parties in their responses/submissions/rejoinders.

G.4 Volume Effect of Dumped Imports and Impact on domestic industry

(a) Demand/ Consumption in India

57. The demand or consumption of the subject goods in India is computed by summing of domestic sales of all the Indian producers and imports from all sources.

Demand	Units	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualised)
Sales of DI	MT	1,396	1,273	1,606	1,818
Sales of Other Indian Producers	MT	600	600	1,140	1,177
Imports from Subject Countries					
Thailand	MT	1,919	1,899	1,828	2,703
Brazil	MT	511	884	980	761
Indonesia	MT	-	-	62	517
Subject Countries	MT	2,430	2,783	2,870	3,981
Others	MT	945	817	640	377
Total Demand	MT	5,371	5,473	6,256	7,353

58. It is noted that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

(b) Import Volumes and Market Share

59. The Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The factual position is as under:

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	POI Annualised
Volumes					
Thailand	MT	1,919	1,899	1,828	2,703
Brazil	MT	511	884	980	761
Indonesia	MT	-	-	62	517
Subject Countries	MT	2,430	2,783	2,870	3,981
Others	MT	945	817	640	377
Total Imports	MT	3,375	3,600	3,510	4,359
Subject Countries Imports in Relation to					
Indian Production	%	95	91	78	97
Demand	%	45	51	46	54
Total Import	%	72	77	82	91
DI Sales	%	174	219	179	219

60. It is seen that
- Imports from the subject countries have increased in absolute terms. It is noted that demand for the subject goods has increased by 37% in the POI since the base year whereas the imports from subject countries have increased by 64%.
 - The share of imports from subject countries in relation to total imports increased over the injury period from 72% to 91%, thus showing a substantial increase in imports throughout the injury period.
 - The imports have increased in relation to production and consumption in India.
 - The imports in relation to domestic sales have increased substantially. It is seen that imports in relation to domestic sales have increased by 45% in the period of investigation since the base year.

G.5 Price Effect of Dumped Imports and Impact on DI

61. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to analyze whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non- Injurious Price (NIP) of the DI have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

(a) Price Undercutting

62. A comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The Authority has compared the landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods.

Price undercutting - Weighted	Unit	Thailand	Brazil	Indonesia	Subject Countries (Total)
Landed Value	Rs/Kg	173	168	165	171
Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	15-25	20-30	10-20

63. It is seen that the landed price of imports from the subject countries were below the selling price of the DI. It is thus seen that imports of subject goods were undercutting the domestic prices.

(b) Price Underselling

64. The Authority has also examined the price underselling by comparing the landed value of imports with NIP of the DI.

Particular	UOM	Thailand	Brazil	Indonesia	Subject Countries
Non Injurious Price	Rs/KG	***	***	***	***
Landed Price	Rs/KG	173	168	165	171
Price Underselling	Rs/KG	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***
Price Underselling	Range (%)	20-30	20-30	20-30	20-30

65. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject countries was significantly lower than the NIP determined for the DI. The injury margin determined for each subject county is positive and significant causing injury to the DI.

(c) Price Suppression and Depression Effects of the Dumped Imports

66. Cost of sales and selling price of the domestic industry have been compared with the landed value of imports to determine whether the dumped imports were suppressing or depressing the domestic prices as detailed below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	103	89	95
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	91	88	92
Landed Value	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	112	111	90

67. It is seen that the landed price is below the cost of sales and selling price. There is a decline in both costs of sales and selling price in the period of investigation. However, it is noted that a decline in selling price is more than the decline in the cost of sales. Thus, the imports were depressing the prices of the domestic industry in the market.

H. Examination of Economic Parameters Relating to DI

68. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the DI should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the DI are analyzed herein below:

Capacity, Production, Capacity Utilization, Sales Volume

69. The performance of the DI with regard to capacity, production, capacity utilization, and sales is as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualised)
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	158	158	182
Production - Plant	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	127	134	218
Production - PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	126	130	150
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	81	84	121
Domestic Sales PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	91	115	130

70. It is seen that

- The petitioner enhanced its capacity over the injury period. The petitioner submitted that the capacity was enhanced in line with the increasing demand of the subject goods in India.
- Performance of the DI has improved in respect of production, capacity utilization, and sales.
- Whereas demand for the product increased by 37% in the POI since the base year, sales of the domestic industry increased only by 30%. While the petitioner was able to increase production of other products, the petitioner was not able to increase production of the product in proportion to the increase in demand.

- d. The petitioner submitted that the domestic industry has been able to increase the sales by compromising on the prices, which resulted in a decline in its profits.

(a) Market Share in Demand

71. The market share of the DI in Indian demand is as shown in the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualised)
Share of petitioner	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>99</i>	<i>95</i>
Share of other Indian producers	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>163</i>	<i>143</i>
Share of Subject Country	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>101</i>	<i>120</i>
Thailand	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>82</i>	<i>103</i>
Brazil	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>170</i>	<i>165</i>	<i>109</i>
Indonesia	%	-	-	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	-	-	<i>100</i>	<i>712</i>
Share of Other Countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>85</i>	<i>58</i>	<i>29</i>
Total Demand	%	100	100	100	100

72. It is seen that the market share of the DI in Indian demand has shown a marginal decline; whereas, the market share of the subject countries has increased over the injury period. There has been a significant decline in the import and share of nonsubject countries. However, the domestic industry has not been able to get any benefit of this in view of the prices at which the subject countries imports have been sold in comparison to the third countries imports.

(b) Inventories

73. The details with regard to average inventories of the DI is as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>146</i>	<i>158</i>	<i>138</i>

74. It is noted that the inventories with the DI increased since base year. However, the level of the inventories in absolute terms is not alarmingly high nor the domestic industry provided any evidence to show that the inventory levels were higher than the norms in this industry.

(c) Profits, Return on Investment and Cash Flow

75. Performance of the domestic industry with regard to profitability, PBIT, return on investment and cash profit is as follows

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualised)
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>89</i>	<i>94</i>
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>91</i>	<i>88</i>	<i>92</i>

Profit/(Loss)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(429)	(104)	(158)
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(392)	(120)	(206)
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(589)	(155)	(310)
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	(406)	188	30
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(533)	(99)	(234)

76. It is seen that:

- The selling price of the DI declined till 2015-16 and increased thereafter in POI. However, the decline in the selling price was more than the decline in the cost of production.
- The domestic industry is suffering financial losses throughout the injury period. The losses with the domestic industry have increased during the period of investigation.
- The cash profits of the DI have also declined over the injury period.
- The domestic industry is faced with a negative return on capital employed throughout the injury period. Further, the performance of the domestic industry deteriorated in respect of return on capital employed over the injury period.

77. It is thus seen that the performance of the DI has deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments.

(d) Employment and Wages

78. Performance of the DI with regard to employment, wages, productivity, and growth is as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualised)
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>107</i>	<i>114</i>
Salary & Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>119</i>	<i>129</i>	<i>127</i>
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>130</i>	<i>150</i>
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>121</i>	<i>131</i>

79. It is seen that there is an increase in employment, wages, productivity per day and productivity per employee.

(e) Growth

80. The table below shows the growth of the company in terms of various parameters was as follows

Growth Compared to Previous Year	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Production	%	-	26	3	15
Domestic Sales Volume	%	-	(9)	26	13
Profit	%	-	(292)	69	(72)

Growth Compared to Previous Year	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cash Profit	%	-	(506)	146	(84)
Selling price domestic	%	-	(9)	(3)	4
Return on Capital Employed	%	-	(14)	14	(5)

81. It is noted that the growth of the domestic industry was negative in respect of profits, cash profits, return on capital employed, and market share, and inventories, whereas the growth was positive in respect of production, domestic sales volume and domestic selling price.

(f) Ability to Raise Capital Investments

82. The Petitioner has stated that the ability to raise fresh investment is not impacted by dumping of the product as investment decisions are long-term decisions and are taken considering present and potential demand for the product under consideration. However, long-term viability of the product under consideration is dependent upon strong profitable business.

(g) Factors Affecting Domestic Prices

83. The petitioner stated that imports are at a price materially below the selling price of the DI. Since the competition in the market is largely between the DI and imports and further since the consumer are buying the product after comparison between the domestic and imported product, it is the import price that is responsible for the decline in the selling prices and consequent decline in price parameters of the DI

I. Conclusion on Injury

84. It is thus seen that there has been an increase in the volume of dumped imports from subject countries in absolute terms. The imports have increased in relation to consumption and production of the product in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have had an adverse price effect in terms of price depression. The domestic industry is suffering significant price underselling. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of market share, profits, cash profits and return on investment. Whereas the demand for the product under consideration has increased over the injury period and its sales volumes and market share has not increased in proportion to increase in demand. Inventories with the domestic industry increased. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

J. The magnitude of Injury and Injury Margin

85. The non-injurious price for the subject goods produced by the DI as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports for each of the co-operative exporter from the subject countries and the injury margin has been determined on a weighted average basis. As for the residual category, the NIP has been compared with the landed value determined on the basis of import data.

Injury Margin

SN	Producer/Exporter	Country	NIP	Landed	Injury Margin		
			Rs/Kg	Rs/Kg	Rs/Kg	%	Range
1	Nitro Chemical Industry Limited / Nobel NC Co., Limited	Thailand	***	***	***	***	15-25
2	Any other than at Sl. No. 1	Thailand	***	***	***	***	35-45
3	PT INTI Celluloseutama / PT Indocera Utama Precisi,	Indonesia	***	***	***	***	20-30

4	Any other than at sl. No. 3	Indonesia	***	***	***	***	30-40
5	All producers	Brazil	***	***	***	***	20-30

K. THREAT OF MATERIAL INJURY

86. The petitioner had also claimed that the imports are threatening material injury to the DI. The Authority has examined various parameters with regard to the threat of material injury as well:

- i. **Increase in imports** - there is an increase in imports from the subject countries in absolute terms as well as in relation to production and consumption. It is seen that imports from the subject countries cover 91% of the total imports. The significant rate of increase of dumped imports into India in POI as compared to preceding year indicates the threat of substantially increased importation. Petitioner submitted that the imports of the product increased further in the post POI.
- ii. **Surplus capacity**- the Authority notes that the capacity of Thailand is 40,000 MT p.a. whereas their estimated domestic demand is around 4000 MT. Thus, the surplus capacities available with Thailand are significant and are almost round 36,000 MT p.a. The Indonesian market is very small and they have set up a plant in Indonesia, the capacity is 4000 MT. This shows that Indonesia has sufficient freely disposable capacity. The total capacity available with Brazil (as per the petitioner) is 38,000 MT p.a. and the consumption is 7000-8000 MT p.a. Such surplus capacity the exporter indicates the increased possible exports to Indian markets given its growing demand, subject to the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- iii. **Inventories**- the Authority has examined the details with regard to inventories provided by the exporters in their responses and it is seen that the level of inventories has been decreased.

87. Examination of information on record shows the dumping has caused injury to the domestic industry. The factors identified above clearly show existence of a threat of further injury

L. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

88. It was further examined whether other following parameters listed under the AD Rules could have contributed to the injury to the domestic industry. It is noted as under:

(a) Volume and Prices of Imports from Third Countries

89. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. It is noted that imports from third countries, barring China are negligible and could not have caused claimed injury to the domestic industry. It is also seen that whereas the share of subject countries in total imports increased from 72% (2013-14) to 91% (POI), the share of non-subject countries declined proportionately. In the case of non-subject countries, imports beyond de minimus limits were reported from Taiwan (in 2013-14 and 2014-15) and China. Imports from Taiwan declined to below de minimus limits in POI. While imports from China were beyond de minimus limits in POI, the volume of imports from China declined steeply over the injury period in both absolute terms and in relation to total imports, production & consumption in India, import price from China after adding prevailing customs duties was significantly higher than subject countries. Further, throughout the injury period, the landed price of imports from China was higher than subject countries and that could not have caused injury to the domestic industry.

(b) Contraction of Demand and Changes in Pattern of Consumption

90. There has been an increase in demand/apparent consumption of the subject goods over the injury period and hence contraction of demand cannot be a factor causing injury.

(c) Developments in Technology

91. Technology for production of the product concerned has also not undergone any change.

(d) Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices

92. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the DI.

(e) Export Performance of the DI

93. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export has not affected the present injury analysis.

(f) Performance of Other Products Produced and Sold by DI

94. The performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the DI's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

(g) Productivity of DI

95. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production and shows an increase. Deterioration in productivity is not a cause of injury to the DI.

(h) Parameters Showing Causal Link

96. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- i. The imports from the subject countries are at dumped prices.
 - ii. Imports are undercutting the prices of the domestic industry, consequently, the DI has reduced their prices far beyond the cost declines.
 - iii. The price depression faced by the domestic industry due to price undercutting has led to a decline in profits, cash profits and ROI of the domestic industry.
 - iv. The volume of imports increased significantly in the POI. While the market share of imports increased, that of the domestic industry declined. Thus, increased lower priced imports are linked to the fall in DI market share

M. USER INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

97. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of Antidumping measures would not restrict imports from the subject countries/ territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
98. It is recognized that the imposition of antidumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the antidumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, the imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

N. Post disclosure submissions of the interested parties**N.1 Views of domestic industry**

99. The domestic industry inter alia submitted as follows

- i. The essential facts include conclusion on injury parameters, conclusion on issues of fact, scope of product, like article and domestic industry, dumping & dumping margin. The decisions on the same need to be informed to the interested parties in the disclosure statement.
- ii. Major customers of the domestic industry preferred to shift to imports due to dumped prices offered by the exporters. The petitioner has enhanced capacities and kept working on increasing the demand for its product in the market. This resultant increase in demand was taken by the exporters as apparent from the increase in market share of the imports.
- iii. Market share of two other producers of the subject goods should be examined separately as one of them has entered the market very recently.
- iv. CIF prices from Thailand are much higher than that of Indonesia and Brazil, however they do not reflect the true prices. Significant “discounts” are offered by NCI & NNC from Thailand.
- v. Of all the imports into India, 41% (1662 MT of PUC) was imported by one user i.e. Esdee Paints, who communicated to the Petitioner, asking for discounts matching the discounts that are being offered on the imported material. The customer has clearly stated that CIF prices should not be considered as there are heavy discounts being offered on the same. Evidence for the same has been placed on record.
- vi. Other major importers during POI including Huber and Siegwerk get post invoicing volume discounts according to the market information. Such discounts do not reflect on the import data or the import price. If required, petitioner would make a statement on affidavit.
- vii. On nearly, 70% of the imports, Thailand have been offering special discounts, thereby making their import price significantly lower than that of Indonesia and Brazil.
- viii. The volume of imports from other countries is much lower than volume of imports from Thailand. As regards Indonesia, while the import price is lower than Thailand, the growth in import from Indonesia is far higher. Imports from Indonesia started only in 2015-16, and the volume increased almost 8-9 times in the POI. Thus, the fact that Indonesian producer reduced import price significantly as compared to Thailand is fully reflected in the quantum increase in import volumes from Thailand.
- ix. The Authority has considered the evidence provided by the petitioner and it has noted that the Gujarat Pollution Control Board had issued a plant closure notice to the petitioner; however, the petitioner soon after issuance of notice complied with the directions issued by the Board and the plant was never shut.
- x. The petitioner enhanced capacities to cater to the demand for the product in the country. However, even when demand increased by 2,897 MT over the period, the petitioner was not able to proportionately increase its sales.
- xi. The domestic industry in view of increase in demand has increased its capacity in 2014-15 and period of investigation. However, the domestic industry was unable to increase its production and sales in proportion to increase in demand.
- xii. Production and capacity utilization has increased upto 2015-16. Thereafter, while production increased, capacity utilization declined in the period of investigation. The production only increased as the petitioner was able to increase the exports; otherwise the petitioners would have faced a significant inventory.

- xiii. Sales have increased only because the domestic industry compromised on the selling price in order to sell the product. Moreover, the domestic industry has not been able to sell the product in proportion to increase in demand.
- xiv. The fact that the sales of domestic industry have got adversely impacted gets readily established by the pattern of sales to various customers. Even when overall sales of the domestic industry have improved, it would be seen that sales of the domestic industry to few customers very steeply declined. These declines in sales are not due to decline in consumption by these consumers. These decline in sales is due to procurement of imported material by these consumers
- xv. Market share of the domestic industry has increased up to 2015-16 and then declined in the POI. The loss of market share is to dumped imports from subject countries. Having gained market share up to 2015-16, and having enhanced capacities for the PUC, there is no reason why the market share of the domestic industry should have declined in the POI.
- xvi. Profitability, PBIT and return on capital employed of the domestic industry declined in 2014-15. However, losses declined thereafter in 2015-16. Losses increased significantly in POI with the dumping of the product in the Country.
- xvii. The result of significant price depression being faced by the Domestic industry is the severe decline in cash profits parameters.
- xviii. Inventories have increased over the injury period. The industry is unable to dispose of its accumulated inventories due to presence of dumped imports.
- xix. Growth of the domestic industry in terms of capacity utilization, selling price, profitability, cash profit, PBIT, ROI has been negative. Growth should have been far better considering the increase in capacity.
- xx. Demand for the subject goods was showing significant increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Consumers have been negotiating the prices with the domestic industry on the basis of import prices. Thus, the principal factor responsible for the domestic industry prices is the landed prices of the subject goods.
- xxi. No other factors, such as export performance, change in technology, performance of other products of the company, conditions of competition or change in pattern of consumption are causing injury to the domestic industry apart from the dumped imports.
- xxii. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, lower import prices are preventing the domestic industry from aligning their prices to the cost of production.
- xxiii. Price undercutting resulted in reduction in the selling prices. As a direct consequence, the domestic industry is suffering decline in cash profits and is faced with increased losses and negative return on investments.
- xxiv. Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices, it is losing its market share. The petitioner has lost sales to its prime customers over the injury period, either completely or substantially.
- xxv. Anti-dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in USD/MT. With no mechanism it is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price. The legislation permits the Authority to impose duty in form and manner as requested.
- xxvi. Duty should be imposed in a manner where it does not become futile. It has been seen historically that duties are circumvented, if not imposed properly. Several CESTAT decisions have modified order of the Authority on grounds of incorrect form of measures.

- xxvii. Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US\$. This is also supported by the rationality involved in the decision of the CESTAT in the matter of Metcoke from China.

N.2 Submissions by exporter, importer and other interested parties

100. The following submissions were made by producers/exporters/importers/other interested parties

- i. PT IUP argued that PCN prepared by the Authority ignores viscosity, which is an important determinant Industrial Nitrocellulose. Viscosity affects cost and has effect on price comparability. Different users require different viscosity. PCN was prepared in the EQR, using Nitrogen content, Form – powder /solution and Viscosity. Any PCN without these characteristics is incomplete and incorrect.
- ii. Margin calculation based on all three factors (including 5% profit) has been provided. Any calculation by removing any one of the characteristics result in unfair comparison.
- iii. The petitioner has calculated the Dumping margin and Injury margin considering Nitrocellulose as a single PUC. Considering all variations as a single product, margin calculated for PT IUP shows no dumping factually.
- iv. Whereas the Domestic Sale Price in the calculation of dumping margin has been considered as weighted average for each category viz. HNP, HNS and LNP; the Export Sale Price has not been considered on similar basis. The statement has considered Export Sale Price PCN wise as per the PCN in Questionnaire Response submitted.
- v. No evidence of injury or threat, as can be seen from the Table in Recital 69. Any claim of injury is flawed as the production capacity of the petitioner increased by 82% in the POI, seeing its peak of growth. Increase in capacity can be seen in sync with incredible performance of its production, capacity utilization and domestic sales volume. Thus, there is not material injury.
- vi. Audited Financial Statements of the Petitioner for POI clearly state that - The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal (FY 2016-17), the company has improved its profitability & the company could invest substantial amounts in Associates indicating there was no financial trouble, in fact it even declared dividend in 2 years (FY 2013-14, 2014-15 and 2015-16).
- vii. Some declining trend including profit of the Petitioner had nothing to do with import of the PUC from Indonesia which contributed insignificant volume to the total import into India or the total demand. If the Petitioner insisted on its claim of injury or threat of injury, this is attributable to its massive expansion of capacity.
- viii. Petitioner suffered no injury and performance was remarkably healthy during the injury period. DGTR is requested to terminate the investigation immediately.
- ix. Petitioner may be deemed to not form part of the Domestic Industry, as it fails to comply with the definition. RoC search of the petitioner shows that Ramdurai Mannachanallur Rajaram (R M Rajaram) was a Key Managerial Person from February 7, 2001 till April 1, 2014. R M Rajaram was also a director with known importers of the investigation during years February 7, 2001 till April 1, 2014 including one (1) year of the POI for injury calculation.
- x. There is substantial difference in quality of the products exported and produced domestically. Petitioner's product is in fibrous form which is substantially different from the chip form of the product exported by the Exporters.

- xi. The Authority, on request of the Petitioners issued instructions to the interested parties, requesting them to respond on various issues of confidentiality, to which the exporters duly complied. However, the claims of the petitioners on excessive confidentiality were not valid.
- xii. The exporters also raised issues on confidentiality claims of the Petitioners, and clarifications are sought on whether the questions raised by Exporters were put to the Petitioners and the appropriate details must be placed on public file and disclosure statement.
- xiii. Authority has found that there was no plant closure as petitioner complied with the directions of the PCB. However, this fact was not disclosed by the Petitioner and investigated by the Authority only after the interested parties pointed it out. This questions the credibility and reliability of the Petitioners
- xiv. The issue should be investigated whether the non-compliance with the requirements of the Pollution Control Board led to inflation in cost or any other self-inflicted injury.
- xv. The exporters deny that measures taken by Thailand are a non-tariff barrier. It is a policy decision that can be taken to WTO by any other member nation. Petitioner does not have ability or inventory to fulfill domestic demand, leave alone exports to Thailand.
- xvi. With regards to public interest of the user industry, Authority should consider whether the Petitioner will be able to meet the demand of domestic consumers with competitive prices as there have been issues with regard to the process of manufacturing, technology and operational efficiency since the start of the injury period.
- xvii. Relevant evidences have been provided to prove that domestic prices in Thailand are distorted, therefore either sales to third country, or cost (plus 5% profit) be taken to calculate normal value. The repeated requests have been rejected by the Authority, and there have been no reasons provided for the same either. The requests have not even been acknowledged in the disclosure. In the interest of natural justice, the requests and the reasons should be mentioned in the Disclosure statement.
- xviii. Prices in Thailand sales prices in Thailand are extraordinarily high on account of the lack of free competition between sources for supply of the product under consideration. Since imports are indirectly prevented from entering the market freely, the limited supply has led to an increase in prices. This has resulted in an isolated market where the price is distorted and therefore not in the ordinary course of trade
- xix. It can be verified that the prices are distorted since prices of Exporters of Thailand is much higher than the normal value determined for the Indonesian cooperating producers. The price of the Exporters in Thailand is also considerably higher than the price of the Exporters to other countries. The Exporters have specifically filed details of their prices to the top three destinations of export other than India, along with complete adjustments, and back-ups from their respective systems
- xx. Since the Authority has not made an assessment on the submission of the Exporters, the calculation of Normal Value and Dumping margin is incomplete. Therefore Authority is requested to reassess normal value in Thailand after disregarding domestic sales and accordingly dumping margin using third country exports or costs.
- xxi. A communication has been made in this regards to the Authority requesting for a meeting to grant Exporters an opportunity to defend their interests.
- xxii. The volume parameters show improvement in performance and price parameters reflect material injury has been continuing well before increase in imports. This indicates that petitioner has always been injured regardless of whether dumping was taking place or not.
- xxiii. Capacity, Production and capacity utilization of petitioner, Domestic Sales of Petitioner and Market Share of Indian producers are all the volume parameters that show substantial improvement in performance.

- xxiv. Imports from Thailand have not affected the Market share of Indian producers.
- xxv. Price parameters have always shown material injury, regardless of dumping. Since the year with the worst injury was 2014-15, where there was no dumping, there is clearly some extraneous factor that has caused injury to the Petitioner.
- xxvi. The cost trend itself is inflated due to the operational inefficiencies of the Petitioner therefore Petitioner has not been able to adjust its price in line with the cost.
- xxvii. Inflated costs of the Petitioners can be verified by the costs submitted by the Exporters, which has remained low due to operational efficiencies.
- xxviii. Thailand prices remain the highest compared to all other countries under investigation. The price undercutting and underselling of imports for Thailand remain the lowest amongst the subject countries.
- xxix. Positive growth in factors such as Employment, Salary and Wages, Productivity per day and productivity per employee can be seen.
- xxx. The statement that “there is no long term viability” remains presumptive as the Petitioner has all along always made a loss whether there is (allegedly) dumping or not. This is further buttressed considering that the Petitioner’s cost is inefficient
- xxxi. Threat analysis by Authority is erroneous – while the imports were always voluminous as compared to dumping sales, it is to be noted that the capacity, production and sales of the Petitioner has remained the highest during the POI even without the protection of any duty.
- xxxii. There appears to be no analysis conducted to indicate that the surplus capacities (if any) would be utilized towards exports to India. Globally chemical plants have voluminous capacity based on varied facts including economies of scale. Thailand caters to domestic as well as export demand and evidence with regards to price clearly shows no reason for dumping.
- xxxiii. The petitioner has not been able to meet the demand of the domestic market. It is also to be noted that China and Taiwan remain a real and apparent threat to the Petitioner not only due to historical reasons but also the capacities are much larger and also the prices remain lower compared to Thailand in the period post the POI.
- xxxiv. The Petitioner has been suffering injury, if any, on account of raw material supply. Production/supply of cotton liners, which is one of the raw materials, is majorly affected by climatic conditions and the same has consequently, impacted the profitability of the Petitioner (owing to the fact that cotton liners is used to produce the PUC).
- xxxv. Petitioner is realizing the same prices as the domestic prices even in export markets, for which there is no proof of suppression / depression or injury. The Petitioner’s alleged injury, if any, is at most caused by the global price trends rather than the subject imports.
- xxxvi. Authority is requested to clarify that losses/injury, if any, in the export market, plant shut down, water shortage etc are not inappropriately passed off to the domestic market’s performance presented by the Petitioner in its injury analysis.
- xxxvii. Exporters reiterate that there is no basis to levy duties in the present investigation, if at all the duties must be recommended, the Exporters request the Authority to kindly consider recommending duties in ad valorem form.
- xxxviii. Most of the injury parameters have been analyzed on POI (Annualized) figures, however for the remaining few; the analysis has been undertaken based on POI figures. Therefore, the injury analysis cannot be said to be of POI. There has been no basis provided for cherry picking data for such analysis.

- xxxix. The above argument has been derived from Article 3.1 of the ADA, Safeguards Panel Report – Indian Certain measures on imports of iron and steel products and the AD Rules. Also, injury analysis has been carried out for POI (A) but the dumping margin has been calculated for the POI. The causal link breaks since there are no facts that show dumping that led to injury during the POI.
- xl. The petitioners have claimed confidentiality on several grounds, which deprives the respondents the opportunity to properly defend their interests. Rule 7(1), Sterlite Industries (India) Ltd. v. DA and Reliance Industries Ltd. v. DA establish the fact that regardless of any objection raised by an interested party, the DA has to be satisfied with the confidentiality claimed by any interested party.
- xli. The claims of confidentiality of the petitioners should not have been granted by the DA as they serve important economic indicators of injury caused. Past investigations have not given confidentiality to parameters such as actual figures for capacity, production, capacity utilization, domestic sales, export sales, etc. wherein a single producer was a petitioner.
- xlii. The Disclosure wrongly notes that there have been no submissions by opposing interested parties on the issue of confidentiality. Respondents have vehemently objected to the excessive confidentiality of the Petitioners.
- xlili. Agreement between DI and Municipality & Irrigation Dept. has not been disclosed to other interested parties, in which case there can be no comments offered to defend interests related to the issues. The said agreement is not available in the public file and it is not clear whether the agreement has been claimed as confidential or non-confidential. The summary of the confidential document or reasoning behind the same has not been provided either. The evidence should not been taken on record in such a situation.
- xliv. The PUC supplied by the DI is of inferior quality as compared to the imports as can be seen from the difference in colour. The imported goods are also more free flowing than the goods of the DI. The PUC being a substance of hazardous and flammable nature such characteristics pose a big risk.
- xlvi. The imported PUC comes packed in fiberboard drums (poor thermal conductivity) whereas the DI packages the same in metal drums, which contribute to the hazard risks associated.
- xlvi. Financial statements of the DI clearly state that the profitability of the DI has increased throughout the injury period. Since the DI is earning profits throughout, it is not possible to have a negative return on capital employed taking into consideration the fact that the DI is a single product company.
- xlvi. Respondents agree with findings of the DA in the disclosure, and highlight that capacity has been increased by 82% in the POI (A) compared to the base year and the capacity utilization has increased by 21% in the same period. This shows that the performance of the DI has improved.
- xlvi. Respondents agree with findings of the DA in the disclosure showing that the inventory levels of the DI are within the industry norms. Also, the DI is able to sell its entire production either in domestic market or exports despite an increase in production. The facts show that there is no injury at all.
- xlix. The finding of the DA on parameters of employment and wages is agreed upon, and should be confirmed in the final findings.
- i. The DI has failed to establish the threat of material injury and the Disclosure is legally erroneous. It has been held that the imports have increased; however, the assertion has been made without any post POI data in support of its claim.
- li. Post POI data from Min. of Commerce & Industry shows that the landed value from Brazil has increased by 10-12% and INR has depreciated by approx. 10% against the USD. The cumulative effect would be that the undercutting and injury margin would be negative in the Post POI data. Hence, there is no threat of material injury.

- lii. The source of information for surplus capacity in Brazil has not been revealed by the DI and therefore it cannot be relied upon. Also, mere surplus capacities does not signify unutilized capacities or are aimed at being diverted to India or exports.
- liii. POI needs revision as the gap is more than 6 months. The argument of the same has been noted in the Disclosure, but there is no finding in this regard.
- liv. The finding of the DA on the fact that non-tariff barriers are beyond the scope of investigation is agreed upon, and should be confirmed in the final findings.
- lv. In case of demand supply gap, dumping can only happen in respect of demand that is being catered to by the DI, and not in the remaining demand that is being fulfilled by the imports. No injury can be claimed on the same.
- lvi. Landed value of imports from Brazil needs recalculation since the respondents are not clear whether basic custom duty has been included in the calculation. The respondent is the sole agent of an exporter from Brazil (70%-80% of total imports from Brazil) and the IQR shows a landed value higher (3%-5%) than the one mentioned in the Disclosure.
- lvii. The respondents reiterate that there exist other factors like significant export orientation of the DI, increase in cost of production, quality and packing issues, and capturing of market share by other domestic producers which have led to a break in causal link. Also, the DA has failed to carry out an injury assessment for the POI.
- lviii. Overall assessment of various parameters indicates that there has been an improvement in the performance of the DI. Thus, any claims of injury or threat to material injury are unfounded.
- lix. There is no injury to the domestic industry. The capacity is enhanced significantly; also production, sales and capacity utilization have shown improvement.
- lx. Decline in profit is not because of imports from Indonesia is not causing any in jury as imports from Indonesia was the lowest.
- lxi. Massive expansion by the petitioner is the real cause of injury being suffered by the domestic industry. The Indonesian exporter has cooperated with the investigation and the calculation being submitted by the Indonesian exporter should be accepted. The calculation of dumping margin, in consistent with the Rule, possibly shows no dumping.
- lxii. Imports from Indonesia are not in competition with the petitioner, Indonesian export is to complement the demand and downstream industry of India. In light of the submissions made the present investigation should be terminated.
- lxiii. The Authority should not levy the anti-dumping duty as the same is against the public interest. The product sold by the domestic industry is of higher price and low uality. If the duty is imposed the users will have no option than to buy the product from the petition.
- lxiv. The petitioner is unreliable and unfavorable as their supply is inconsistent and fails to adhere to the delivery schedules.
- lxv. There is only one manufacturer of the product under consideration in India I.e. Nitrex Chemical, the other producer is very small and does not sell good quality product. Nitrex Chemical charges high price of the product and enjoying monopoly in the market.
- lxvi. Pencil is an education product and the government has kept import duty zero from Indonesia and Thailand so that Nitrocellulose is easily available to the customers.

- lxvii. Imposition of duty will increase the cost and will hamper the exports of the product under consideration.
- lxviii. The domestic industry retails the relevant grade of the product at much higher rate and the quality of the product does not match the international standards. Imposition of duty will lead the user industry to limited option.
- lxix. Imposition of duty will not only lead the user industry to compromise with its commercial interest but also with the quality of downstream product.
- lxx. The petitioner is highly unreliable as they fail to deliver orders within due delivery date and ultimately jeopardize the interest of all the stake holders.

Examination by Authority

101. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the interested parties are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and properly addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The authority further considers as follows with regard to issues raised by the interested parties.
- i. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding.
 - ii. As regards the argument of injury and causal link, the Authority notes that the injury analysis carried out hereinabove is self-explanatory to establish that the dumping has caused injury to the domestic industry.
 - iii. As regards the argument of dumping margin calculation of PT IUP, it is clarified that since the exporter has provided the information on type wise basis, the Authority in order to ensure fair comparison has compared the export price of the types exported to India with the domestic selling prices of the same respective types.
 - iv. Public statements like annual reports of companies do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.
 - v. As regards the issue of eligibility of the petitioner, it is noted that the petitioner was not related to the importer or any exporter of the alleged dumped article during period of investigation. In view of the above, the Authority did not find appropriate to treat petitioner as ineligible domestic industry.
 - vi. As regards argument on quality of product manufactured by domestic industry, it is noted that since the product manufactured by the domestic industry is held as like article to the product being imported into India and the two are used interchangeably by the users/importers, such issues raised by the interested parties without concrete evidence to establish the same, could not be applied.
 - vii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties
 - viii. As regards argument on public interest, it is noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers
 - ix. With regard to the contention that the domestic prices of Nobel NC Co., Ltd and Nitro Chemicals Industry Limited should not be considered for determination of normal value, it is noted that the selling

price has been determined on the basis of the records kept by the producers, maintained as per GAAP in Thailand, and the same is found to be appropriate for evaluating whether the sales in domestic market have been made in the ordinary course of trade. In any case, the exporter themselves have admitted that the Thai Army is regulating only the storage and usage of the product concern and the suppliers are required to obtain license before supplying the product in Thai market. Licensing procedure is common in most of the countries where products is of or can be used for explosives or any other hazardous substance. Mere licensing procedure does not mean that the domestic selling prices cannot be in the ordinary course of trade.

- x. As far as the argument of demand supply gap is concerned, it is noted that if the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value to capture the market. As regards, argument that China and Taiwan are real threat, it is reiterated that imports from Taiwan declined to below de minimus limits in POI. While imports from China were beyond de minimus limits in POI, the volume of imports from China declined steeply over the injury period in both absolute terms and in relation to total imports, production & consumption in India, import price from China after adding prevailing customs duties was significantly higher than subject countries. Further, throughout the injury period, the landed price of imports from China was higher than subject countries and that could not have caused injury to the domestic industry.
- xi. As regards the submission concerning form of duty, the Authority notes that as per the Anti-dumping Rules, the mandate of the Designated Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, suitability of the form of the anti-dumping measures is decided by taking into consideration the facts of a case.

O. Recommendation

- 102. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal values.
 - b. The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries.
 - c. The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.
- 103. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all the interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of duty is necessary to offset dumping and injury. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non-injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.
- 104. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table given below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from subject countries from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government for a period of five years.

DUTY TABLE

SN	Sub heading or Tariff Item	Description on of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3912	Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose Damped in Isopropyl Alcohol having Nitrogen content in the range of 10.7% to 12.2%.	Thailand	Any country including Thailand	Nitro Chemical Industry Limited or Nobel NC Co., Ltd	0.567	Kg	US\$
2.	3912	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than at 1.	0.906	Kg	US\$
3.	3912	-do-	Any country other than Thailand	Thailand	Any	0.906	Kg	US\$
4.	3912	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT INTI Celluloseutama	0.235	Kg	US\$
5.	3912	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than at 4.	0.475	Kg	US\$
6.	3912	-do-	Any country other than Indonesia	Indonesia	Any	0.475	Kg	US\$
7.	3912	-do-	Brazil	Any country including Brazil	Any	0.646	Kg	US\$
8.	3912	-do-	Any country other than Brazil	Brazil	Any	0.646	Kg	US\$

105. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

SUNIL KUMAR, Add. Secy. & Director General